◆ मई, 2022 ◆ मूल्य: 35/-

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से अनुप्राणित

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका

अभ्युदय वात्सल्यम्

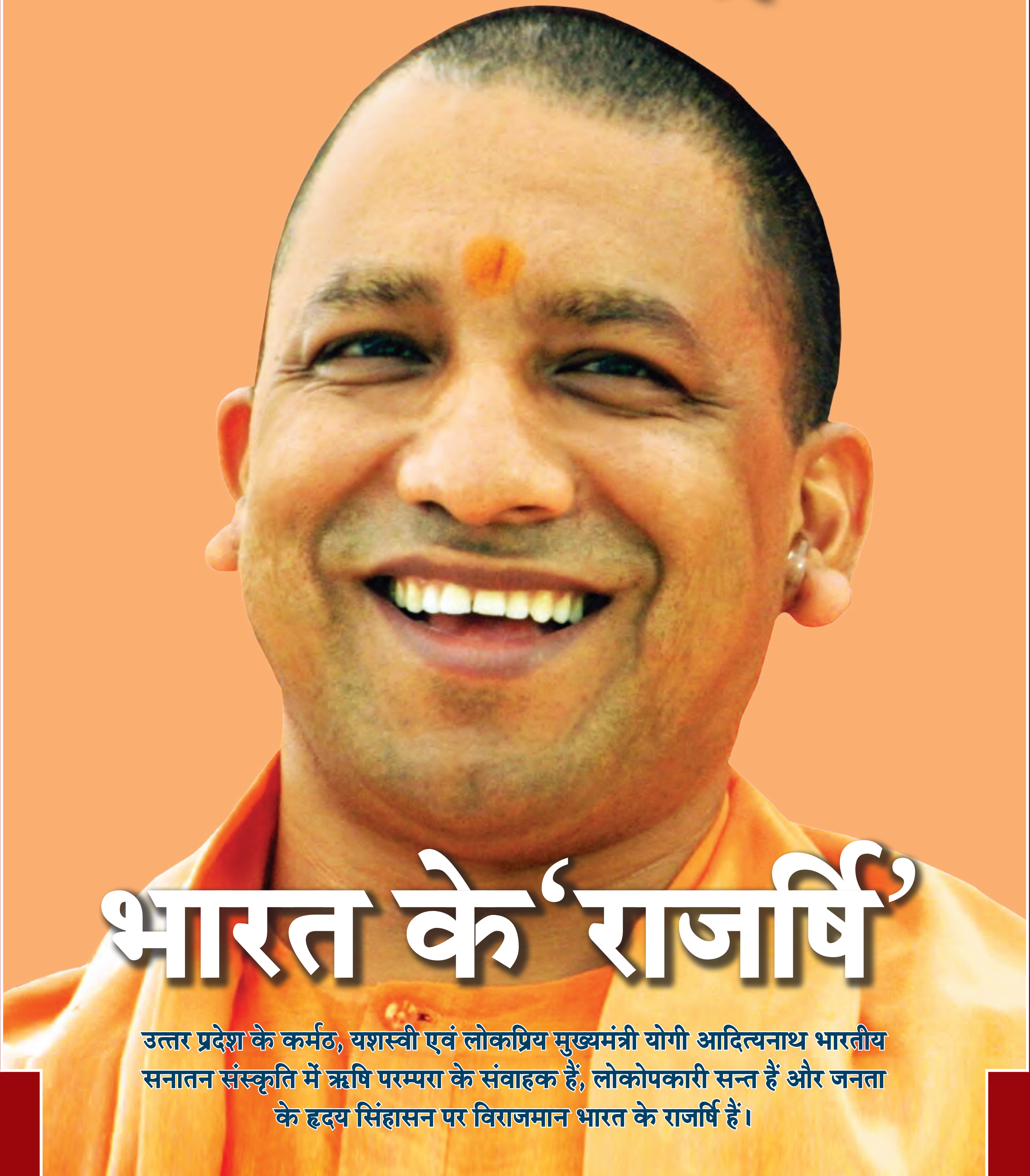

भारत के 'राजर्षि'

उत्तर प्रदेश के कर्मठ, यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय सनातन संस्कृति में ऋषि परम्परा के संवाहक हैं, लोकोपकारी सन्त हैं और जनता के हृदय सिंहासन पर विराजमान भारत के राजर्षि हैं।

Breakfast se pehle...
subah bolo Good knight
Good knight
GOOD HABIT HAI
For more information log onto subahbologoodknight.com

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से अनुप्राणित

अभ्युदय वात्सल्यम्

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका

▪ वर्ष-14 ▪ अंक-10 मई , 2022 ▪ मूल्य- 35/-

संस्थापक सम्पादक : कृपाशंकर तिवारी
प्रधान सम्पादक : आलोक रंजन तिवारी
प्रबन्ध सम्पादक : शिवा तिवारी
विधिक सम्पादक : आशुतोष मिश्रा
लखनऊ ब्यूरो : हरिभजन शर्मा
विज्ञापन प्रबंधक - संजय सिंह
ग्राफिक डिजाइनर - अनमोल शुक्ल , अनिल मशालकर
फोटोग्राफर - हार्दिक रामगुड़े , राहुल पारकर

पत्राचार कार्यालय: आर - 2/608 , आरएनए प्लाजा , निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर , राम मंदिर रोड , गोरेगांव (प.) , मुंबई - 400104

एनसीआर ब्यूरो : 748, वास्टो महागुन मॉडर्न , सेक्टर - 78 , नोएडा - 201 305.

लखनऊ ब्यूरो : 101 , श्रद्धा विहार कॉलोनी , चिन्हट , लखनऊ - 226 028 .

कृपा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कृपाशंकर तिवारी द्वारा विनय ग्राफिक्स, युनिट नम्बर 13 , रवि इंडस्ट्रियल प्रेमायसेस, महाकाली केव्स रोड , अन्धेरी (पूर्व) , मुंबई - 400093 से मुद्रित एवं आर - 2/608 , आरएनए प्लाजा , निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर , राम मंदिर रोड , गोरेगांव (प.) , मुंबई - 400104 से प्रकाशित।

सम्पादक : आलोक रंजन तिवारी
पंजीकृत कार्यालय: आर - 2/608 , आरएनए प्लाजा , निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर , राम मंदिर रोड , गोरेगांव (प.) , मुंबई - 400104

दूरभाष: 022 -26771428 / 9167404760 / 7800611428
ई-मेल: kst@avmagazine.co.in
वेबसाइट : www.avmagazine.co.in

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं से सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका में प्रदर्शित समस्त पद अवैतनिक हैं। पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र मुंबई होगा।

आन्तरिक

आवरण
भारत के 'राजर्षि' योगी आदित्यनाथ
पृष्ठ 06

अवॉर्ड
अभ्युदय वात्सल्यम् वीमेन अचीवर्स अवॉर्ड
पृष्ठ 28

विशेष लेख
हिंदुत्व और योगी का सुशासन मॉडल
पृष्ठ 10

देश-विदेश
हाईकोर्ट को मिलेंगे 15 जज कॉलेजियम से मिली मंजूरी
पृष्ठ 60

06 भारत के "राजर्षि" योगी आदित्यनाथ

विशेष आलेख

40 भारतीय उद्योग जगत के गौरव बाबा कल्याणी

46 बेमिसाल बैंकिंग का अप्रतिम उदाहरण इंडसइंड बैंक

52 मणिपुर के विशेष संदर्भ में उत्तर पूर्व और उसके बदलाव की कहानी

56 बदलता सिनेमा इसका इतिहास और निहितार्थ

योगी का अर्थशास्त्र और शहरी विकास

आलोक रंजन तिवारी

योगी की वेशभूषा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अक्सर ही ऐसे व्यक्ति के रूप में सीमित कर दिया जाता है जो विकास के पुराने मॉडल के हिमायती होंगे और जो आधुनिक विकास प्रतिरूपों के प्रति संकोची स्वभाव रखते होंगे। लेकिन दिलचस्प बात है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने साथ रूढ़ कर दी गई छवि के विपरीत जाकर विकास के आधुनिक मानदंडों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

वस्तुत:, मुख्यमंत्री योगी के सत्ता में आने से पहले उत्तर प्रदेश का शहरी विकास देखने के लिए लखनऊ, इटावा या मैनपुरी का विशेष दौरा करना पड़ता था जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। वहीं विगत पाँच वर्षों में योगी आदित्यनाथ के प्रभावी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपने बुरे अतीत को काफी पीछे छोड़ विकास के शानदार रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की नई इबारतें लिख रहा है।

चाहे देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो या पिछली सरकार में हाशिये पर रखे गए अमेठी, सुल्तानपुर और गाजीपुर जैसे छोटे शहरों को विकास के मानचित्र पर स्थापित करने की बात हो, योगी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री योगी ने कभी भी विकास या किसी भी समाज के हितों के लिए न तो किसी स्थान विशेष से भेदभाव किया और न ही समाज के किसी वर्ग विशेष से बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी शहरों की बेहतरी के लिए समान भाव से कार्य किया, चाहे वो शहर जनपद मुख्यालय हो, कमिश्नरी हो या राजधानी।

> चाहे देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो या पिछली सरकार में हाशिये पर रखे गए अमेठी, सुल्तानपुर और गाजीपुर जैसे छोटे शहरों को विकास के मानचित्र पर स्थापित करने की बात हो, योगी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है।

इसका सबसे बेहतरीन और आदर्श उदाहरण अमेठी शहर है जो कि विरोधियों का आम चुनावों में पसंदीदा निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है और पूर्व में निर्वाचित उम्मीदवारों ने अमेठी की भोलीभाली जनता को कई वर्षों तक ठगने का काम भी किया। अमेठी की विकट परिस्थितियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अमेठी में शाम 6 बजे के बाद रोडवेज की बसों का संचालन बंद हो जाता था और वहाँ के आम लोगों का प्रदेश के बाकी हिस्सों में आवागमन शाम होते ही बंद हो जाता था। बमुश्किल 8 से 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती थी। स्वास्थ्य केंद्रों की ऐसी दशा कि वहाँ मनुष्य क्या पशुओं का भी इलाज सम्भव न था। लेकिन, आज अमेठी की बदली हुई तस्वीर हर किसी को देखनी चाहिए। पूरे दिन-रात बिजली, हर घर को पानी, बेहतरीन सड़क जैसी हर उस सुविधाओं का इंतजाम मुख्यमंत्री की ओर से किया गया जो मानवीय गरिमा को बनाये रखने हेतु आवश्यक हैं।

अब प्रयागराज का ही उदाहरण देख लीजिए। शहरों का सुन्दरीकरण कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए देश भर के नीति नियंताओं को प्रयागराज के खूबसूरत उदाहरण से सीखना चाहिए। गंगा -यमुना -सरस्वती के पवित्र संगम के किनारे बसा प्रयाग वो ऐतिहासिक संगम नगरी है जहाँ हमारे ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इस पवित्र धरती पर गिरी थी। इसीलिए यहाँ पर पवित्र और भव्य महाकुम्भ मेले का आयोजन प्रत्येक बारहवें वर्ष किया जाता है। पहले की सरकारों ने जहाँ कुम्भ मेला क्षेत्र का दायरा अत्यंत ही संकुचित बना रखा था, वहीं मुख्यमंत्री योगी ने इसका दायरा 2019 में बढ़ाकर 32 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में कर दिया जो अब तक के इतिहास में सबसे विशाल कुम्भ मेले का आयोजन था। इस भव्य और विशाल आयोजन में देश-दुनिया के करोड़ों लोंगो का आगमन हुआ और पवित्र संगम में डुबकी लगाई और सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिकोण से जो अभूतपूर्व इंतजाम किये गए उसकी गूंज आज भी देश के कोने-कोने में सुनाई पड़ती है। बाकी प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व को भी भीड़ के बेहतरीन मैनेजमेंट के गुर उस कुम्भ मेले से सीखना चाहिए।

प्रयाग ही वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान राम अपने वनवास के समय प्रवास के स्थान के मार्गदर्शन हेतु भारद्वाज मुनि के आश्रम आये

फोटो : पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे

और जहाँ भारद्वाज मुनि में उन्हें चित्रकूट प्रवास करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारद्वाज मुनि के तपोस्थली प्रयागराज का जो विकास किया है, उसे वहाँ देखकर हर कोई महसूस कर सकता है। भारद्वाज मुनि और भगवान श्री राम से जुड़ी मान्यताओं के कारण लोग प्रयागराज से चित्रकूट तक की यात्रा करते हैं और चित्रकूट प्रवास करते हैं लेकिन अच्छी सड़कें न होने के कारण पहले लोग बमुश्किल ही जा पाते थे। सरकारी बसों का परिचालन भी नगण्य ही था लेकिन योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट तक सड़कों का बेहतरीन संजाल स्थापित किया, जिससे इन इलाकों के निवासियों का जनजीवन तो आसान हुआ ही साथ ही धार्मिक महत्व के कारण होने वाली यात्राओं के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के नये अवसरों का भी जन्म हुआ है। मुख्यमंत्री योगी के कुशल मार्गदर्शन में प्रयागराज की संकरी गलियों और सड़कों का चौड़ीकरण, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण सुनियोजित तरीके से किया गया है।

प्रयागराज से हवाई सेवाओं की शुरुआत कर योगी जी ने प्रयाग के साथ-साथ आस-पास के जिलों जैसे-जौनपुर, प्रतापगढ़ के निवासियों की बहुप्रतीक्षित आकांक्षाओं की पूर्ति कर उनके कठिनाई भरे जन-जीवन को आसान कर दिया। इसी कड़ी में हमें प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसे गाजीपुर और बलिया की बात जरूर करनी चाहिए। मंगल पांडेय, जयप्रकाश नारायण जैसे नायकों की धरती बलिया ने तो विकास शब्द का नाम 2017 के पहले शायद ही सुना हो। योगी जी ने उसे समझा भी और उसे स्थापित भी किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर। बलिया को सिर्फ प्रदेश की राजधानी से ही नहीं जोड़ा गया बल्कि जो एक्सप्रेसवे की कड़ियाँ बनाई गई हैं, उससे यह राष्ट्रीय राजधानी से भी जुड़ गया। उसी प्रकार राजा सुहलदेव और वीर अब्दुल हमीद की धरती को पूर्व की सरकारों के द्वारा माफियाओं की पैदावार बनाकर छोड़ दिया गया था। सुविधाओं के नाम पर गाजीपुर शून्य से भी नीचे था लेकिन योगी ने गाजीपुर को सर्वप्रथम देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी से बेहरतीन सड़क संजाल से जोड़ दिया, जिससे गाजीपुर के लोग आसानी से हवाई नेटवर्क से भी जुड़ कर प्रदेश और देश के विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गए और आज तो पूर्वांचल एक्सप्रेस्वे भी वीरों की धरती गाजीपुर को नमन करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच रही है।

ये योगी की ही दूर दृष्टि का परिणाम है कि गोरखपुर, अयोध्या, कुशीनगर, देवरिया जैसे छोटे-छोटे शहर आज विकास के शानदार सफर पर आगे बढ़कर देश के बड़े-बड़े शहरों से कदमताल कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भ्रमण और दर्शन हेतु जाने वाले बुद्ध के देश-दुनिया के उनके अनुयायियों को कुछ वर्ष पूर्व तक सोचना पड़ता था कि कैसे सुविधाजनक तरीके से वहाँ पहुँचा जाए लेकिन ये योगी का कर्मफल ही है कि कुशीनगर आज पूरी दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई नक्शे पर आ चुका है। ऐसे ही विद्वेष और तुष्टिकरण की भावना के कारण ही भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हमेशा से राजनेताओं के द्वारा तिरष्कृत ही रही लेकिन सत्ता में आते ही योगी ने सर्वप्रथम अयोध्या नगरी के गौरव को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू कर दिया और आज पूरे देश-दुनिया के सनातनी अपने गौरव को उसी भव्य रूप में वापस पाकर आंनद विभोर हैं। ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही था कि चाहे शहरी विकास हो या अवसंरचना सुदृढ़ीकरण या फिर पर्यटन के लिहाज से बुनियादी सुविधाओं की बहाली, योगी सरकार इस संदर्भ में सफल रही है।

◆◆◆

कृपाशंकर तिवारी

भारतीय भू-मण्डल पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसी विभूति हैं जो 'राजर्षि' (राजा + ऋषि) के समस्त सद्गुणों से सुसम्पन्न हैं। आप भारत वर्ष के गौरव हैं, अनमोल रत्न हैं।

भारत के 'राजर्षि' योगी आदित्यनाथ

भारतीय सनातन संस्कृति में 'राजर्षि' एक ऐसे राजा को कहते हैं जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, राजा हो, ऋषि हो, योगी हो, सन्त हो, महात्मा हो...। 'राजर्षि' मात्र एक शब्द, उपाधि, सम्मान या उपमा मात्र नहीं है। 'राजर्षि' एक ऐसे प्रजावत्सल, प्रतापी, तपस्वी, योगी शासक (राजा) की परमोच्च आत्मिक स्थिति की परिचायक दिव्य पद, स्थिति और महिमा है, जिसकी नीति, सुकीर्ति और पराक्रम प्रजा (जनता) को निर्भयता, सुख-शांति एवं समृद्धि प्रदान करती हो। योगी आदित्यनाथ जी उपरोक्त समस्त दिव्य गुणों से सुसम्पन्न ऐसे ही राजनेता हैं, लोकहित साधक-उपासक, शासक हैं, मुख्यमंत्री हैं, जनतंत्र के राजा हैं। हालांकि, जनतंत्र में कोई

* लोक कल्याणरत एक सन्यासी मुख्यमंत्री

राजा नहीं होता है किन्तु जनतांत्रिक देश में निर्वाचित सरकार के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री को एक राजा की ही स्थिति,अवस्था, उत्तरदायित्व एवं हैसियत प्राप्त होती है, जो राजतंत्र में राजा को प्राप्त होती थी। योगी जी सर्व प्रथम एक सन्यासी हैं, योगी हैं और उसके बाद देश के सुविशाल राज्य उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री हैं।

भारतीय भू–मण्डल पर वैदिक काल में सर्व प्रथम ऋषि विश्वामित्र को राजर्षि की उपाधि(पद) प्राप्त हुई थी। विश्वामित्र जी पहले राजा थे और बाद में ऋषि हुए। योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक बहुत ही अद्भुत सुसंयोग और सुखद स्थिति यह है कि आप सबसे पहले सन्यासी हैं, योगी हैं और बाद में हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप वास्तविक रूप में करोड़ों जनता के दिलों पर राज करने वाले **महाराजा** हैं।

यह भारत का परम सौभाग्य है कि हमें योगी आदित्यनाथ के रूप में, एक महान विभूति प्राप्त है जो देश - दुनिया के लिए मुख्यमंत्री के रूप में एक आदर्श हैं, प्रेरणा हैं। वैदिक काल से इतिहास साक्षी है कि जब एक तपस्वी, योगी सत्तासीन होता है तो राज्य में सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण प्राकृतिक रूप से निर्मित होने लगता है।

एक शासक, राजा या मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी अपेक्षा यही की जाती है कि वह समदर्शी, सत्यभाषी, ईमानदार, निष्पक्ष व कर्मठ हो, सन्त की भांति उसकी दृष्टि में सब समान हों, छोटा–बड़ा, ऊंच–नीच,भेद भाव की भावना न हो और एक पिता की भांति राज्य की जनता का पालक–पोषक–रक्षक हो। योगी जी उपरोक्त सभी गुणों के स्वामी हैं। यह युगांतरकारी सुखद तथ्य और सुसंयोग ही है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे राजा बनने के पूर्व से ही समदर्शी हैं क्योंकि योगी –ऋषि समदर्शी होते ही हैं। योगी जी का हृदय और भावनाएं अत्यंत निर्मल हैं, आप निर्भयता की साक्षात् मूर्ति हैं, तपस्वी हैं।

* पूजा - अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ

आप जन-जन के स्वाभिमान-सम्मान एवं हितों के रक्षक हैं, आपका ह्रदय करुणा- दया से ओत-प्रोत है क्योंकि आप एक योगी हैं, सन्त हैं, ऋषि हैं। किन्तु, दुष्टों के लिए आपका ह्रदय वज्र के समान कठोर भी है। लोककल्याण हेतु माता-पिता, घर-परिवार आदि का त्याग करने वाले योगी जी साक्षात् **त्याग मूर्ति** हैं, नि:स्वार्थ सेवा भावना के प्रकाश पुंज हैं। ऐसी दिव्य विभूति यदि हमारे सेवक हैं, शासक है, मुख्यमंत्री हैं तो निर्विवादित है कि आप देश-प्रदेश की करोड़ों जनता के दिलों पर राज करने वाले असली राजा हैं। यह भारत का परम

योगी जी के यौगिक - राजनैतिक जीवन का यथार्थ पक्ष यह है कि आप सत्य का आग्रह करने वाले, अन्याय-अत्याचार तथा शोषण के विरुद्ध धर्म युद्ध का शंखनाद करने वाले वीरव्रती संन्यासी हैं।

सौभाग्य है कि हमें योगी आदित्यनाथ के रूप में, एक महान विभूति प्राप्त है जो देश - दुनिया के लिए मुख्यमंत्री के रूप में एक आदर्श हैं, प्रेरणा हैं। वैदिक काल से इतिहास साक्षी है कि जब एक तपस्वी, योगी सत्तासीन होता है तो राज्य में सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण प्राकृतिक रूप से निर्मित होने लगता है। वर्तमान में इस तथ्य की सत्यानुभूति उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आज प्रदेश की जनता निर्भय है, सुरक्षित है और प्रादेशिक जन जीवन में सुख-शांति और खुशहाली की बयार बह रही है जो भविष्य में और अधिकता स्पष्टता के साथ तथा और अधिक गहराई के साथ अनुभव की जा सकेगी। प्राणिमात्र से प्रेम करने वाले आप मानवता के पथ प्रदर्शक महापुरुष हैं। राष्ट्रहित के विषयों पर हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहने वाले

गोरक्षपीठाधीश्वर भारत के गर्व हैं, अनमोल रत्न हैं। योगी जी के यौगिक – राजनैतिक जीवन का यथार्थ पक्ष यह है कि आप सत्य का आग्रह करने वाले, अन्याय– अत्याचार तथा शोषण के विरुद्ध धर्म युद्ध का शंखनाद करने वाले **वीरव्रती संन्यासी** हैं। आपका आत्मबल अत्यंत प्रचंड है और इस प्रचंड आत्मबल का आधार सत्य, प्रेम एवं करुणा पर आधारित आपका यौगिक जीवन और ऋषित्व ही है।

मन, वाणी और कर्म में एकरूपता ही योगी जी की सबसे बड़ी शक्ति है, जो जनता के मन में उनके प्रति विश्वास और आदर की भावना की वृद्धि करता है। किसी भी राजनेता के प्रति जनता का विश्वास ही वह सबसे बड़ी पूँजी और शक्ति है, जो लोकतंत्र में जनता जनार्दन और उसके सेवक (जननेता, राजनेता) के सम्बन्धों को सुदृढ़ आधार प्रदान करता हुआ समाज और नेता के बीच गरिमापूर्ण स्थिति की स्थापना करता है। प्राय: देखा जाता है कि अधिकारी, मंत्री या मुख्यमंत्री अपने आसन पर विराजमान रहते हैं और फरियादी जनता जिसे जनार्दन (भगवान) कहा जाता है, वह हाथ जोड़े कतार में खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री ने इस परम्परा को तोड़ा।

भारतीय धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता को अपने विराट व्यक्तित्व में समेटे हुए एक सन्यासी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को जनता देखती है कि उनका सेवक, उनका संन्यासी मुख्यमंत्री जनता 'जनार्दन' के पास खुद जाता है, खड़े होकर उनकी बात सुनता है और जनता जनार्दन के रूप में आसन पर विराजमान रहती है। ऐसा हृदय स्पर्शी दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि हमें वास्तविक रूप में 'जनता का सेवक मुख्यमंत्री' प्राप्त हुआ है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। आप स्वयं में अद्वितीय हैं। योगी जी एक संत हैं और स्वाभाविक रूप से आप परमोच्च आत्मिक स्थिति के स्वामी हैं। आप सत्यानुरागी, सत्यभाषी, कर्मयोगी सन्यासी हैं और लौकिक रूप से अलौकिक गुणों को धारण करने वाले ऋषि हैं, योगी हैं। आपके व्यक्तित्व में सभी रसों का अद्भुत सम्मिश्रण है–जिसमें वात्सल्य, करुण एवं वीर रस की प्रधानता है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को धन्य किया है।

आपके कृतित्व – व्यक्तित्व एवं सेवाओं पर एक वृहद् ग्रंथ लिखे जाने की आवश्यकता है, इस अकिंचन द्वारा निकट भविष्य में इस आवश्यकता पूर्ति की प्रबल संभावना है।

राम राज्य की अवधारणा को साकार करने हेतु भगीरथ प्रयास करने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मठ, यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय सनातन संस्कृति में ऋषि परम्परा के संवाहक हैं, लोकोपकारी सन्त हैं और जनता के हृदय सिंहासन पर विराजमान भारत के 'राजर्षि' हैं। आपका विराट व्यक्तित्व वंदनीय है, अभिनंदनीय है, महिमामंडनीय है। ◆◆◆

* अपने गुरुदेव महंत अवैद्यनाथ जी के साथ योगी आदित्यनाथ

* कन्या पूजन और गोमाता को आत्मिक प्रेम करते हुए योगी आदित्यनाथ

सन्नी कुमार

हिंदुत्व और योगी

का सुशासन मॉडल

राजनीतिक संस्कार की बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू पहचान को लेकर न केवल अत्यधिक मुखर हैं बल्कि नीतिगत स्तर पर भी इसे बरतने के हिमायती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण वाली धारा से शासन को अलग किया और केवल नागरिक को इकाई मानकर प्रशासन चलाया। साथ ही इससे आगे बढ़कर उन सांस्कृतिक प्रतीकों को भी शासन व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जिनसे अब तक बचा जा रहा था।

तमाम अटकलों और कयासों के बाद योगी आदित्यनाथ ने दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया है। यह एक ऐतिहासिक बात है। ऐतिहासिक इस संदर्भ में कि बीते कई दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार शासन में लौट पाया है और इस संदर्भ में भी कि योगी ने हिंदुत्व और सुशासन के जिस युग्म के सहारे स्वयं को प्रोजेक्ट किया वो काफी सफल रहा। निश्चित ही यह राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने वाला होगा। इन दोनों पहलुओं - हिंदुत्व और सुशासन- को योगी के विशेष संदर्भ में देखने की आवश्यकता है।

हिंदुत्व और योगी

राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर अकादमिक बहसें जितनी सघन रही हैं, उतना ही जटिल इसका राजनीतिक अनुप्रयोग भी रहा है। वस्तुत: यह कहना चाहिए कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के सहारे **हम कौन** की खोज बौद्धिक और राजनीतिज्ञ दोनों का प्रिय कार्य रहा है। **हम कौन हैं** के विचार से ही राजनीति का सांस्कृतिक क्षेत्र निर्धारित होता है। भारतीय राजनीति का उदाहरण देखें तो यह मोटे तौर पर दो भागों में बँटी नजर आती है। एक तरफ कांग्रेस,

सपा व अन्य दल हैं जो राष्ट्र की पहचान के लिए लगभग एक जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा जैसे दल हैं जिनके लिए राष्ट्र अलग अर्थ रखता है। इन वैचारिक अंतरों से ही राजनीतिक मुद्दों की भिन्नता भी तय होती रही है। तो मूल सवाल है कि यह अंतर क्या है?

अंतर के कई बिंदु हैं लेकिन इन सबके मूल में **अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक** संस्कृति का द्वैत है, जिसे सेकुलरवाद के नाम पर संचालित किया जाता रहा है। पहली श्रेणी यानी कांग्रेस व सपा की बात करें तो अपने राजनीतिक प्रयोग में ये बहुसंख्यक यानी हिंदुओं के धार्मिक मुद्दों को एक सायास दूरी से बरतते रहे और अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों से सायास निकटता स्थापित करते दिखे। यह सरकारी नीतियों और राजनीतिक मुहावरों, दोनों माध्यमों से होता रहा। वस्तुत:, अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी इसी विचार के इर्द-गिर्द हुई। इतना ही नहीं सेकुलरवाद को लेकर जिस तरह की बौद्धिक धारणाएं निर्मित हुईं, उसमें एक तरफ तो अल्पसंख्यकों के नितांत धार्मिक मसलों को राज्य के संरक्षण से सुरक्षित किया गया तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक जनता से न केवल धार्मिक रूप से तटस्थ रहने की अपेक्षा की गई बल्कि उनके जीवन से धर्म का महत्व कम करने की भी कोशिश की गई। यह अनायास नहीं है कि हिंदू संस्कृति के हर प्रतीकों को सेकुलरवाद के विरुद्ध देखने की चेष्टा की गई तथा इनके आचारों-विचारों को पोंगापंथी का नाम देकर उपहास उड़ाया गया। दूसरी तरह इन्हीं प्रतिमानों पर अल्पसंख्यक विशेषत: इस्लाम को अपनी धार्मिक अस्मिता को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और ऐसे हर प्रोत्साहन को सेकुलरवाद के नैतिक आवरण से ढंका गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था में सेकुलरवाद का उपयोग धर्म का राजनीति से अलगाव के रूप में कम तथा राष्ट्रीय अस्मिता को बहुसंख्यक सांस्कृतिक निरंतरता से अलगाने में अधिक हुआ।

लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था में सेकुलरवाद का उपयोग धर्म का राजनीति से अलगाव के रूप में कम तथा राष्ट्रीय अस्मिता को बहुसंख्यक सांस्कृतिक निरंतरता से अलगाने में अधिक हुआ।

दूसरी तरफ की राजनीति को एक व्यक्ति के माध्यम से विश्लेषित करने की कोशिश करें तो वो हैं-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इस संदर्भ में अपनी पार्टी भाजपा से भी कहीं अधिक स्पष्टवादी हैं। राजनीतिक संस्कार की बात करें तो योगी अपने हिंदू पहचान को लेकर न केवल अत्यधिक मुखर हैं बल्कि नीतिगत स्तर पर भी इसे बरतने के हिमायती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण वाली धारा से शासन को अलग किया और केवल नागरिक को इकाई मानकर प्रशासन चलाया। साथ ही इससे आगे बढ़कर उन सांस्कृतिक प्रतीकों को भी शासन व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जिनसे अब तक बचा जा रहा था। इस संदर्भ में काशी कॉरीडोर का निर्माण, अयोध्या में राममंदिर निर्माण में सक्रियता और इसी अनुरूप शहरी विकास का नियोजन, शहरों/ जगहों के नाम परिवर्तन तथा धार्मिक स्थलों को केंद्र में रखकर अवसंरचना विकास जैसी बातें इस बात को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी वैचारिकी को ईमानदारी से निभाया है। राष्ट्रवाद का यह स्वरूप अच्छा है या बुरा यह विवेचना का अलग प्रश्न हो सकता है किंतु इतना तो तय है कि योगी ने सरकार का नेतृत्व करते हुए इसे निभाया।

सार रूप में कहें तो योगी उन नेताओं में हैं जिन्होंने भारतीय सेकुलरवाद का चितेरा होने के लोभ का संवरण किया और इसलिए वो दारा शिकोह को किनारे कर

योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का आदेश जारी किया था। आखिर ये बदला हुआ नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम ही है कि जो संस्था कल तक बाहुबलियों की जी हुजूरी में लगा था वही आज उन माफियाओं के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है।

औरंगजेब की परंपरा का महिमामंडन नहीं करते, बल्कि वो खुलकर उसके धार्मिक उन्माद को राजनीतिक मजबूरी की आड़ में नैतिक साबित करने वालों के विरुद्ध बोलते हैं। वो राजनीति की मुख्यधारा के चलन को नकारते हैं और शिवाजी जैसे व्यक्तित्व को सांप्रदायिक सिद्ध करने की कोशिश का प्रतिकार करते हैं। इतना ही नहीं जब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" को गाने से भी सिर्फ इसलिए इंकार कर दिया जाता हो क्योंकि इसमें हिंदू भाव है और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने को भी हिंदूवादी भावना के नजरिये से देखा जाता हो, वैसे में योगी आदित्यनाथ इन प्रतीकों के प्रति संपूर्ण श्रद्धा दिखाते हैं। ये उदाहरण साफ तौर पर इंगित करते हैं कि कैसे सेकुलरवाद का इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन से हिंदू प्रतीकों को शिथिल करने के लिए किया जा रहा है। अर्थात् सेकुलर होने की अनिवार्य शर्त यह मान ली गई है कि वो हिंदू परंपरा से मुक्त हो। योगी ने इस प्रकार जिस सेकुलर समाज को रचने की कोशिश की जा रही थी, उसका मुक्त स्वर से विरोध किया। वो इस धारा के उपासक हैं जो मानता है कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद ये देश के धार्मिक ग्रंथ नहीं वरन ज्ञान परंपरा के स्रोत हैं। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य धार्मिक उपदेशक नहीं वरन भारतीय मूल्यों के सर्जक हैं। वंदे वातरम और जन-गण-मन हिंदू गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। एक राष्ट्र के रूप भारत हिंदू संस्कृति से रचा बसा है और सेकुलरवाद की ओट लेकर इसे अलगाया नहीं जा सकता। यह अविच्छिन्न है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए।

योगी और सुशासन

एक दिलचस्प बिंदु यह भी है कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था के प्रति रवैये को अक्सर कटघरे में खड़ा किया जाता है। बुल्डोजर प्रतीक को ही लें तो कहा जाता है कि सरकार कुछ अधिक ही सख्ती से पेश आ रही है और यह सामान्य चलन नहीं रहा है। गौर से देखें तो योगी सरकार की यह नीति भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दायरे से ही निकलती प्रतीत होती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न केवल अपने प्रतीकों के प्रति सजगता का आग्रही होता है बल्कि वह राष्ट्र और समुदाय की सुरक्षा के प्रति भी उतनी ही निष्ठावान होने की अपेक्षा करता है। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नायक अक्सर इस मामले में कठोर दिखाई देते हैं और ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। कानून व्यवस्था को लेकर अन्य उपाय भी इसका ही विस्तार है।

जिस प्रदेश में बाहुबल के राजनीतिक संस्थानीकरण की शुरुआत हुई हो वहाँ कानून व्यवस्था के मायने कैसे होते होंगे इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन, योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का आदेश जारी किया था। आखिर ये बदला हुआ नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम ही है कि जो संस्था कल तक बाहुबलियों की जी-हुजूरी में लगा था वही आज उन माफियाओं के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है। यह उसी भावना का विस्तार है कि शासन से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, सभी को विधि के शासन के अनुकूल ही रहना होगा।

एक आंकड़े के हवाले से देखें तो पूर्ववर्ती सरकार के शासन में प्रदेश में प्रति वर्ष औसतन 150 दंगों का रिकॉर्ड तो देश में अपराध सांख्यिकी की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पास है। यानी प्रत्येक तीसरे दिन उत्तर प्रदेश का आम जनमानस दंगों की आग में झुलसता था और मौका परस्त सरकार सत्ता के नशे में मदहोश जनता को उसके भाग्य के सहारे छोड़ तमाशबीन बनी रहती थी। ऐसे एक दो नहीं बल्कि असंख्य दंगे और साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने के मामले घटित हुए, जिनमें किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई होने के बजाय समाज में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को उस समय सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के स्तर से बचाया गया और इसका आंकड़ा न तो किसी सरकारी संस्था के पास है और न किसी सामाजिक संस्था के पास।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार सत्ता में आयी तो यह कहा जा सकता है कि तब से उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य के लिए

योगी के हिंदुत्व मॉडल पर तो खूब चर्चा होती है लेकिन उनके सुशासन पक्ष पर कम बात होती है जबकि जनता के बीच वो इन दोनों ही वजहों से लोकप्रिय है।

यह अति आवश्यक है कि शासन के स्तर से समय-समय पर ऐसी कार्य योजनाएं तैयार की जाए जिससे राज्य में हमेशा विधि व्यवस्था विद्यमान रहे और लोगों का भरोसा भी संविधान और विधि के शासन के प्रति बना रहे। ऐसे ही समाज के सकारात्मक आशाओं और आवश्यताओं के अनुरूप योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक महत्व रखने वाले कई योजनाओं की घोषणा की और उसका क्रियान्वयन एक निश्चित समय के अंदर सुनिश्चित किया।

सामाजिक सुरक्षा की भावना को मजबूत करने लिए मुख्यमंत्री रहते हुए योगी ने सर्वप्रथम मिशन शक्तिकरण अभियान की शुरुआत की। गृह विभाग के द्वारा संचालित इस अभियान में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षाकर्मियों की समुचित भागीदारी के साथ एंटी रोमियो स्क्वॉयड का गठन किया गया। मिशन शक्तिकरण अभियान के तहत ही प्रदेश के गृह विभाग प्रदेश द्वारा अन्य 24 प्रमुख विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। मिशन शक्तिकरण योजना के तहत महिला सुरक्षा के साथ - साथ समाज के कमजोर, पिछड़े तबके एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से आने वाले लोगों को सम्बल प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़कर सरकार के द्वारा संचालित होने वाली प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का समुचित लाभ उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश के सभी 75 जिलों के तहसीलों, ब्लॉकों एवं पंचायतों को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में अवैध रंगदारी और वसूली से तंग आकर पलायन कर रहे उद्यमियों-व्यापारियों को उनके कारोबार की सुरक्षा की सम्पूर्ण गारंटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विशेष आदेश से स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (विशेष सुरक्षा बल) का गठन किया गया है, जो प्रदेश में सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी उद्योगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस विशेष कार्य बल के गठन से सामान्य पुलिस प्रशासन की चुनौतियाँ भी कम हुई हैं, जो उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में उठानी पड़ती थी। साथ ही पुलिस बल को अतिरिक्त काम के बोझ से मुक्त करने के लिए और उनकी कार्य क्षमता को बनाये रखने के लिए पिछले चार साल में डेढ़ लाख सिपाही के पदों पर भर्तियां हुई हैं।

इन सब के अलावा प्रदेश में 40 नये पुलिस थाने और तकरीबन डेढ़ दर्जन से अधिक पुलिस चौकियों का गठन योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है ताकि दूरदराज में रहने वाले लोगों की पहुँच आसानी से पुलिस सहायता केंद्रों तक हो सके। यदि आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश में विगत दो तीन साल में गम्भीर अपराधों में कमी भी आई है और समाज के लिए अवांछनीय अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा मामलों का त्वरित अन्वेषण कर निर्धारित समय के अंदर ही न्यायालय में चार्जशीट दायर की जा रही है ताकि पीड़ितों को जल्दी न्याय मिल सके।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बात करें तो एनसीआरबी की हाल के रिपोर्ट के अनुसार देश भर में जहाँ 38 लाख मामले दर्ज किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी मात्र 12 प्रतिशत है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। जबकि, देश की कुल आबादी का 20 प्रतिशत हिस्सा यहाँ निवास करता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी जहाँ पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण आयी है, वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा चलाये जा रहे रात्रि सुरक्षा कवच योजना,पिंक बूथ योजना ,पिंक बस योजना, मिशन शक्तिकरण अभियान जैसे सुधारात्मक कार्यक्रमों के फलस्वरूप महिलाओं के प्रति सामान्य नजरिये में सकारात्मक बदलाव आया है।

इसी क्रम में हत्या और किडनैपिंग जैसे गम्भीर अपराधों की बात करें तो दिल्ली स्थित एनसीआरबी के हालिया आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे अपराधियों के भय से मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय दंड संहिता के अंर्तगत हत्या जैसे कठोर दंड के पूरे देश में तीस हजार के करीब मामले दर्ज किए। गए जिसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ पैंतीस सौ के करीब मामले दर्ज किये गए यानी कुल आंकड़ों का 10 प्रतिशत। इतना ही नहीं हत्या के मामले में चार्जशीट फाइल करने की दर की बात करें तो जहाँ राष्ट्रीय औसत 75 प्रतिशत है वही उत्तर प्रदेश में 77 प्रतिशत। तो ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका अपराधियों के संदर्भ में संरक्षणकर्ता से बदलकर संहारकर्ता की हो चुकी है और ये बदलाव स्वभाविक तौर पर सरकार के बदले नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति की ओर इशारा करते हैं।

इन सभी आँकड़ों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि योगी के हिंदुत्व मॉडल पर तो खूब चर्चा होती है लेकिन उनके सुशासन पक्ष पर कम बात होती है जबकि जनता के बीच वो इन दोनों ही वजहों से लोकप्रिय है। और ये दोनों ही तत्व एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। ◆◆◆

म्यूच्युअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें.

आशुतोष मिश्रा

पिछली बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के तुरंत पश्चात योगी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के ऋण माफी की घोषणा की थी। इस ऋण माफी योजना के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जिसमें प्रदेश के 86 लाख किसानों के एक लाख रुपये तक के फसली ऋणों को माफ कर दिया गया।

किसानों के लिए सदैव तत्पर योगी आदित्यनाथ

अब जबकि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं तब इस प्रश्न को फिर से देखना उचित ही है कि योगी सरकार का किसानों से कैसा रिश्ता रहा है? इस प्रश्न पर विचार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव के पहले किसान मुद्दे पर ही योगी सरकार को सबसे अधिक घेरा गया था। अब जबकि यह तय हो गया है

फोटो : किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

कि किसानों ने अपनी आस्था योगी में ही व्यक्त की है, इसे समझ लेना भी जरूरी होगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में कुल 2 करोड़ 32 लाख कृषक परिवार निवास करते हैं और एक कृषक परिवार में औसतन छह सदस्य हैं। इतनी विशाल आबादी की कृषि पर निर्भरता के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान कहलाती है। उसमें भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसके जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान पच्चीस प्रतिशत है। ऐसे में सत्ता पर आसीन नीति निर्माताओं का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा निर्मित कार्य योजनायें किसानों के हितों पर आधारित हों।

पिछली बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के तुरंत पश्चात योगी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के ऋण माफी की घोषणा की थी। इस ऋण माफी योजना की अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जिसमें प्रदेश के 86 लाख किसानों के एक लाख रुपये तक के फसली ऋणों को माफ कर दिया गया, जिसमें अधिकांश लघु एवं सीमांत किसान थे। योगी जी के इस शानदार निर्णय से उत्तर प्रदेश के किसानों का आत्मविश्वास वापस लौट आया और उन्हें पहली बार ये आभास हुआ कि सरकार यदि चाहे तो किसानों के घर भी खुशहाली आ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भलीभांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जब किसान

फोटो : किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

आत्मनिर्भर रहेंगे, कर्जों से मुक्त रहेंगे तभी उत्तर प्रदेश अन्नदाताओं के आशीर्वाद से खुशहाल रहेगा।इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी किसानों के कल्याण निमित्त योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या फसलों के समय पर सिंचाई को लेकर थी क्योंकि अब वर्षा के सहारे खेती अत्यंत ही मुश्किल है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए योगी जी की सरकार ने विगत चार वर्षों में दशकों से लंबित 17 जल परियोजनाओं को पूरा किया है जो पिछली सरकारों के उपेक्षापूर्ण

उत्तर प्रदेश वह उत्तम प्रदेश है, जिसकी मिठास पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है यानी पूरे देश में होने वाले गन्ने के कुल उत्पादन का 50 फीसदी और चीनी का 38 फीसदी हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में होता है।

रवैये का दंश झेल रहा था। गोंडा, बहराइच,श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती,महराजगंज, गोरखपुर सहित अन्य आस-पास के जिलों के किसानों के लिए सरयू नहर परियोजना ईश्वरीय वरदान साबित हुई है। समय पर सिंचाई की व्यवस्था होने से इन जिलों में फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। ठीक इसी तरह अर्जुन सहायक परियोजना बाँदा, हमीरपुर, महोबा जिले किसानों के लिए समृद्धि का सागर लेकर आयी है, वहीं 46 वर्षों से लंबित बाणसागर परियोजना के पूरे होने से मिर्जापुर,भदोही, प्रयागराज,वाराणसी जिलों के किसानों की सिंचाई की समस्या का पूर्णत: समाधान हो चुका है।

जिन इलाकों में नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, उन इलाकों के किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए यूपी फ्री बोरिंग योजना के माध्यम से निशुल्क बोरिंग कर सिंचाई

नि:संदेह हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति योगी जी के मार्गदर्शन में काफी सुदृढ़ हुई है। किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं और प्रदेश के अन्य लोगों के साथ कदमताल कर रहे हैं।

की व्यवस्था की गई है। इस योजना का लाभ उन लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जा रहा है, जिनके पास 0.2 हेक्टेयर से कम कृषि जोत है। अभी तक 3 लाख गरीब किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों के हितों के लिए समर्पित योगी सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर भारी सब्सिडी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत प्रदान कर रही है। उन्नत किस्म के कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है और ऐसे शोधोपरांत निर्मित वैज्ञानिक उपकरणों के इस्तेमाल से खेती अब कम पूँजी और थोड़े श्रम लागत के कारण अधिक फायदे का विषय बन रही है। इस तरह से योगी जी ने किसानों से जो वायदा चुनावों के वक्त किया था की उनकी आय दुगुनी कर देंगे वो साकार रूप लेती नजर आ रही है। प्रदेश के किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में एक है **उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना**। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर वाटर पंपों का आवंटन किया जा रहा है और इन वाटर पंपों के देखभाल तथा मरम्मत का जिम्मा अगले पांच वर्षों तक राज्य विद्युत विभाग के पास है। इसके लिए किसानों को किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। योगी जी के इस कदम से लाखों किसानों को भारी भरकम आने वाले बिजली बिलों से छुटकारा मिला है।

उत्तर प्रदेश वह उत्तम प्रदेश है, जिसकी मिठास पूरे भारत वर्ष में व्याप्त है यानी पूरे देश में होने वाले गन्ने के कुल उत्पादन का 5० फीसदी और चीनी का 38 फीसदी हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। इस मिठास के पीछे प्रदेश के 48 लाख गन्ना किसानों की दिन-रात की मेहनत है, जिसकी बदौलत प्रदेश में 119 चीनी मिलें अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही हैं। ऐसे में किसी भी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि गन्ना किसानों को उनके मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्रदान करे और ये काम योगी सरकार ने वर्ष 2017 -2021 तक महज चार वर्षो में गन्ना किसानों को 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये भुगतान कर किया भी है, जो पिछली सरकार से 58 हजार करोड़ रुपये अधिक है। प्रदेश में गन्ना के साथ-साथ धान और गेंहूँ का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और ये योगी जी के कृषि योजनाओं का ही परिणाम है कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में पहले पायदान पर है और धान में दूसरे पर। योगी सरकार अन्नदाताओं के उपज का भरपूर मूल्य देने में विश्वास करती है। इसी कड़ी में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2०21 के फसली वर्ष के लिए 1888 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित कर 55 लाख मीट्रिक टन की सरकारी खरीददारी की गई। इतना ही नहीं बल्कि 2017-2021 तक 244 लाख मीट्रिक टन धान की खरीददारी वर्तमान योगी सरकार के द्वारा की गई जो कि पिछली सरकार से सीधे दो गुना ज्यादा है। वहीं गेंहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसली वर्ष 2021 के लिए 1925 रुपये निर्धारित किया गया।। 2017-2021 तक 210 लाख मीट्रिक टन गेंहूँ सीधे किसानों से खरीद की गई जो पिछले सरकार के 94 मीट्रिक टन खरीददारी से दो गुने से भी ज्यादा है। योगी सरकार अन्नदाताओं को उनके उपज के दाम सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रान्सफर कर रही है, जिससे उनको अपने हक के रुपयों के लिए कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं रह गयी है और न ही बिचौलियों की अब कोई भूमिका रह गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलायी जा रही कल्यानकारी योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक सुनिश्चित हो तथा कृषि सम्बन्धी नवाचारों के इस्तेमाल से किसानों का काम आसान और अत्यधिक लाभप्रद हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से पिछले वर्ष **किसान कल्याण मिशन योजना** की शुरुआत की गई। 6 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक संचालित इस योजना को तीन चरणों में बारी-बारी से प्रदेश के सभी 824 विकास खण्डों में व्यापक तौर पर चलाया गया। इस योजना के अंतर्गत कृषि मेले का आयोजन कर किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती के जहाँ तौर तरीके बताये गए, वहीं नए कृषि उपकरणों के परिचालन औऱ उनके इस्तेमाल सम्बन्धी जानकारियां भी विशेषज्ञों के द्वारा दी गयी। इसी दौरान सरकार के द्वारा किसानों के हित में चलायी जा रही अन्य सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी किसानों को दी गयी। इसलिए नि:संदेह हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति योगी जी के मार्गदर्शन में काफी सुदृढ़ हुई है। किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं और प्रदेश के अन्य लोगों के साथ कदमताल कर उत्तर प्रदेश को विकास के दौड़ में अग्रणी बनाये हुए हैं। ◆◆◆

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और योगी सरकार

कमला शंकर मिश्र

राज्य सरकार ने भी अयोध्या को केंद्र में रखकर अनेक विकास योजनाएँ निर्मित की हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का निर्माण इसी निरंतरता का एक पक्ष है।

किसी भी भू-भाग के शासक के मूल्यांकन का एक आधार यह भी होता है कि वो स्थानीय संस्कृति के कितना अनुकूल है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भू-भाग के लिये तो यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसलिये आवश्यक ही है कि योगी आदित्यनाथ को भी इस कसौटी पर परखा जाए कि वो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के कितने समीप हैं। खासकर, इस संदर्भ में कि जिस सनातन विरासत को लेकर भारतीय जनता

पार्टी अपना दावा जताती है, उसको लेकर उसके मुख्यमंत्री कितने सजग हैं, यह गौर करने वाली बात है।

फोटो : अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

सनातन की त्रिवेणी

वस्तुत: उत्तर प्रदेश इसलिए खास है क्योंकि यह कई महत्त्वपूर्ण सनातन प्रतीकों का केंद्र है। आस्थावान सनातनियों के लिए यहाँ काशी है जो एक अक्खड़ किंतु उल्लासपूर्ण जीवन शैली का पर्याय है तो मृत्यु के प्रति सहज जीवन-बोध का प्रतीक भी। भगवान शिव की इस नगरी को सनातन धर्म का निचोड़ कहा जा सकता है। फिर इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी है। अयोध्या यानी भगवान राम की नगरी। सनातन परंपरा में मर्यादा का चरम जिस व्यक्तित्व में मिलता है, वो हैं राम। अयोध्या भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता का एक अनूठा और गौरवशाली केंद्र रहा है। इसके साथ ही देखें तो सनातन धर्म के एक और अवतार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा भी उत्तर प्रदेश में ही है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदू संस्कृति की त्रिवेणी है।

वस्तुत: उत्तरप्रदेश की इस सांस्कृतिक समृद्धि का भारतीय पहचान को व्याख्यायित करने में बहुत कम उपयोग होता रहा है। जिस सेकुलर विचार के नाम पर भारतीय मानस को परिभाषित करने की कोशिश होती रही, उसमें अयोध्या, काशी और मथुरा कहीं नहीं थी। इसे नितांत निजी धार्मिक प्रतीक मानकर भारतीयता की परिभाषा से विलग कर दिया गया था, जबकि दूसरे अन्य प्रतीक गंगा-जमुनी तहजीब के नाम पर प्रश्रय पाते रहे। इस स्थिति में आमूल बदलाव तब आया जब 2014 में केंद्र की सरकार बदली और पाँच साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता भी बदली। यहाँ से एक भारतीय के रूप में **हम कौन हैं** की खोज का नया अध्याय शुरू हुआ। और यह कोई प्रतिगामी, आक्रामक और विरोधी न होकर आस्थावान, विनम्र और निष्ठावान है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे देखते हैं। हालाँकि, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तय हुआ किंतु जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें सक्रियता दिखाई, शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और सनातनी वेशभूषा धारण की, उससे यह भाव प्रत्यक्ष हुआ कि अब शासन के लिए आदर्श-नागरिक होने की अर्हता गैर-हिंदू व्यवहार नहीं रहा। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी अयोध्या को केंद्र में रखकर अनेक विकास योजनाएँ निर्मित की हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का निर्माण इसी निरंतरता का एक पक्ष है। ऐतिहासिक निरंतरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किये बिना सांस्कृतिक निष्ठा के भौतिक स्वरूप को आधुनिक समय के अनुकूलन करना ही काशी कॉरीडोर के मूल में रहा है। निश्चित ही यह भी दर्शाता है कि कैसे शासन सनातन परंपरा की परिधि में अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कर रहा है। मथुरा के लिए तीर्थ विकास परिषद के गठन को भी इसकी निरंतरता में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्कृति प्रेरित शहरी विकास का नियोजन, शहरों/ जगहों के नाम परिवर्तन तथा धार्मिक स्थलों को केंद्र में रखकर अवसंरचना विकास जैसे अनेक उदाहरणों की चर्चा की जा सकती है। इन सभी उदाहरणों का निष्कर्ष यही है कि उत्तर प्रदेश जिस सनातन समृद्धि को धारण करता है, उसे अखिल भारतीय पहचान प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

उत्तर प्रदेश इसलिए खास है क्योंकि यह कई महत्त्वपूर्ण सनातन प्रतीकों का केंद्र है। आस्थावान सनातन धर्मियों के लिए यहाँ अयोध्या, काशी और मथुरा है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदू संस्कृति की त्रिवेणी है।

संस्कृति अनुकूल नामकरण

इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज करना हो, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नामांतरण पं. दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर करना हो या फिर फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या, इन प्रयासों का एक वर्ग हमेशा-हमेशा से विरोध करता आया है कि इसका औचित्य क्या है? तो आइये! इसके औचित्य को समझते हैं कि क्यों सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिये ऐसा करना अनिवार्य ही है। अंततः यह संस्कृति ही है जिसमें राष्ट्र का प्राण बसता है।

नाम में क्या रखा है। अगर हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी पुकारेंगे तो उसकी खुशबू कम नहीं होगी। जूलियट के हवाले से कही गई शेक्सपियर की यह बात उस संदर्भ में तो प्रतीक प्रतीत होती है जब गुण के सामने नाम के महत्त्व को गौण करने का औचित्य सिद्ध करना हो लेकिन यह उक्ति अपनी पहचान में रूढ़ हो चुके किसी नाम के ऐतिहासिक संदर्भ की अवहेलना भी करता है। खासकर यह नाम किसी शहर का हो तो उस नाम का अपना एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है, जिससे विलग उसकी पहचान नहीं की जा सकती। और यह ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ एक प्रतीक के रूप में राजनीतिक महत्त्व भी रखता है। दरअसल, शहर भौतिक उपस्थितियों का समुच्चय भर नहीं होता बल्कि यह उस विशिष्ट संस्कृति का द्योतक भी होता है जो समय के साथ वहाँ विकसित होती है। इस प्रकार एक शहर की पहचान उसके सभ्यताई विकास और सांस्कृतिक विशेषता, दोनों के साथ रूढ़ हो जाती है और यही वजह है कि जैसे ही किसी शहर का नाम हम सुनते हैं तो उसकी एक स्पष्ट तस्वीर हमारे आँखों के सामने उभर आती है। मसलन, नालंदा का नाम सुनते ही शिक्षा के एक केंद्र के रूप में उसकी पहचान उभर जाती है तो बनारसी शब्द एक मनमौजी संस्कृति को निरूपित करता है। ऐसे ही अन्य शहरों या प्रतिष्ठानों के साथ भी होता है। लेकिन, क्या हो अगर किसी राष्ट्र को उसकी ऐतिहासिकता से विलग कर दिया जाए? उसके सांस्कृतिक पहचान को शिथिल करने की कोशिश की जाए? या फिर उसे नई पहचान के साथ गढ़ने की कोशिश की जाए? इन सभी प्रयासों का एक ही परिणाम होगा कि नागरिक चेतना सांस्कृतिक निरंतरता से भिन्न हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे प्रतीकों के संरक्षण का प्रयास हो। नामांतरण की कोशिश को भी इसी सन्दर्भ में देखने की ज़रूरत है।

नामकरण की प्रवृत्ति किसी एकल प्रक्रिया का उत्पाद न होकर अलग-अलग ऐतिहासिक कृत्यों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है।

वस्तुतः अतीत के अन्याय को समाप्त कर या यूँ कहें कि इस अन्याय को आधार मानकर वर्तमान में प्राचीन-ऐतिहासिक स्मृतियों के निर्माण की प्रवृत्ति वैश्विक है। अक्सर देश या शहरों के नाम ऐसे ही अन्यायपूर्ण स्मृतियों को जताते हैं, जिन्हें वर्तमान सरकार द्वारा बदलकर ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। ऐतिहासिक अन्याय की निर्मिति के पीछे कई वजहें हैं। जब किसी देश पर लंबे समय तक औपनिवेशिक सत्ता कायम रहती है तो वह स्थानीय पहचान और अस्मिता को दरकिनार करते हुए देश/शहरों पर अपने अनुकूल नाम थोप देती है। इसी प्रकार यदि शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच धार्मिक अंतर मजबूत हो और यह धार्मिक अंतर शासन को आधार भी प्रदान करता हो तो कालांतर में शासित वर्ग द्वारा उस दौर की घटनाओं को धार्मिक अन्याय के रूप में चिह्नित किया जाने लगता है। फिर कई जगहों पर देशज जातियों को समाप्त कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया होती है। दुनिया भर में इन्हीं आधारों पर ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

औपनिवेशिक गलतियों को ठीक करने की कोशिशों को देखें तो भारत में ही बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे नामों को बदला गया। इसी प्रकार आज़ादी के पूर्व जिम्बॉबे देश का नाम रोडेशिया था जो ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी के सेसिल रोड्स के नाम पर रखा गया था। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाते ही जिम्बाबे ने औपनिवेशिक

नाम भी बदल लिया। सीलोन से श्रीलंका, वर्मा से म्याँमार, सियाम से थाईलैंड इत्यादि ऐसे ही परिवर्तित नाम हैं जो औपनिवेशिक पहचान त्यागने के उद्देश्य से बदले गए। कुछ नाम इसलिये बदले गए क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति को ठीक प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। उदाहरण के लिये तुर्की का कुस्तुनतुनिया शहर जो एक ईसाई कॉन्स्टेनटाइन के नाम पर था उसे इस्लामी चरित्र के अनुरूप बदलकर इस्ताम्बुल कर दिया गया। बॉयटॉन (Bytown) और यॉर्क (York) से परिवर्तित होकर क्रमशः ओटावा और टोरंटो बने कनाडाई शहरों के पीछे भी यही धारणा थी कि पुराने नाम देशज संस्कृतियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। कुछ देशों में वैचारिक क्रांति के कारण भी नाम बदले जाते हैं। उदाहरण के लिये, रूस में साम्यवादी क्रांति संपन्न होने के बाद साम्यवादी नेताओं के नाम पर लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद जैसे शहर बनाए किंतु 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो पुनः लेनिनग्राद को सेंट

पीटर्सबर्ग और स्टालिनग्राद को वोल्गोग्राद कर दिया गया। सिर्फ शहरों ही नहीं बल्कि सडक़, हवाई अड्डे, पहाड़ इत्यादि के भी नाम भी बदले जाते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो बाकायदा दक्षिण अफ्रीका ज्योग्राफिकल नेम काउंसिल नामक आयोग ही बना है जो नामकरण को सांस्थानिक रूप प्रदान करता है ।

ऐसे अलग-अलग उदाहरणों के उल्लेख का एकमात्र उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि नामकरण की प्रवृत्ति किसी एकल प्रक्रिया का उत्पाद न होकर अलग-अलग ऐतिहासिक कृत्यों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। परंतु इन सबके मूल में जो एक बात रेखांकित करने वाली है वह यह कि लगभग हर मामले में राष्ट्रीय भावना तथा सांस्कृतिक अनुराग इन परिवर्तनों के सबसे प्रभावी कारकों में रहा है। जब कोई राष्ट्र सचेत रूप से यह महसूस करने लगता है कि अतीत के किसी हिस्से में बाह्य हस्तक्षेप के द्वारा उसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक निरंतरता भंग हुई थी तो वह निश्चित ही उसे दोबारा पाने की कोशिश करता है। भारतीय संदर्भ में भी नामांतरण के पीछे यही तत्त्व सर्वाधिक प्रभावी है। खासकर जब से केंद्र में वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई है ऐसे प्रतीकों के प्रति सजगता बढ़ी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पूरे नैतिक बल के साथ ऐसे बदलाव को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। नामांतरण के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि आज भी देश के कई हिस्सों में शहरों/रेलवे स्टेशनों आदि के नाम उन आंक्राताओं के नाम पर हैं जिसने वहाँ के वैभव को नष्ट करने का काम किया था। बिहार के बख्तियारपुर से अच्छा उदाहरण और क्या होगा! जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था उसके नाम पर आज वह जगह जानी जाती है। आखिर इससे हम संस्कृति और इतिहास के किस पक्ष को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों का एक साफ मकसद दिखाई देता है कि एक पराजित राष्ट्र की स्मृति को इस तरह वैधता देना कि नागरिक बोध स्वयं ही नई ऐतिहासिकता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। यह कोशिश सफल न हो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति की ओर लौटें। इन्हें फिर से पाने के हर संभव प्रयास करें। नामांतरण ऐसा ही एक प्रयास है। ऐसे और प्रयास करने होंगे।

● उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पूरे नैतिक बल के साथ नामकरण जैसे बदलावों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं।

(लेखक सामाजिक-राजनीतिक चिंतक एवं पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं)

◆◆◆

ग्रामीण विकास के लिए
समर्पित योगी आदित्यनाथ

– शिवा तिवारी

> मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रबलता के साथ कार्य कर रही है कि गांवों के विकास से ही विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है और तभी विकसित भारत के सपने को भी साकार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि यहाँ व्यापक ग्रामीण जनसंख्या भी विद्यमान है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ग्रामीण विकास को लेकर योगी की ऐसी क्या नीति थी कि जनता ने दोबारा इन्हें अपना नेता चुन लिया?

वस्तुत:, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 77 प्रतिशत यानी लगभग 15 करोड़ लोग प्रदेश के 97,941 गांवों में निवास करते हैं। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का यह प्रमुख दायित्व है कि वो अपनी विकास योजनाओं का निर्माण इस विशाल आबादी के हितों को केंद्र में रखकर करे। 2017 से पहले जो सरकार प्रदेश में चुनकर आती थी, उसके विकास का एजेंडा समग्र न होकर क्षेत्र विशेष या कहें कि एक–दो शहरों तक ही सीमित होता था और प्रदेश के गांवों की ओर तो सरकार और उनके मातहतों ने कभी देखना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन, 2017 में सत्ता में पहली बार आई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछली सरकारों के संकुचित एजेंडों को दरकिनार कर पूरे प्रदेश के विकास पर बल देने वाली योजनाओं का निर्माण किया, जिसके तहत ग्रामीणों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास आधारित बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में योगी ने ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे – सड़क, बिजली, पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम किया। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश के हजारों गांव पक्की सड़कों की सुविधा से वंचित थे। बरसात के दिनों में नदियों में आने वाले भीषण बाढ़ के चलते होने वाले अत्यधिक मिट्टी कटान के कारण नदियों के समीप बसे गांवों का प्रदेश के बाकी स्थानों से सम्पर्क पूरी तरह भंग हो जाता था लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। बड़े पैमाने पर बांधों के किनारों की ऊंचाइयों को बढ़ाया गया और नियमित कटान वाले स्थानों पर पक्के निर्माण कर प्रत्येक वर्ष इस नाम पर होने वाली लूट को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। अब तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी एनएच के तर्ज पर हॉटमिक्स पद्धति के अनुसार कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण सड़कें भी गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ बन रहीं हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत सड़कों के निर्माण और रखरखाव के मामले में भी उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में अव्वल है। प्रदेश में सड़कों का जाल कुछ इस तरह से विकसित किया गया है जिससे प्रत्येक गांव की प्राथमिकता के तौर पर ब्लॉक एवं तहसील कार्यालयों के साथ जनपद कार्यालयों तक सरलता से पहुँच सुनिश्चित किया गया है। इससे दैनिक कामकाज से आवागमन करने वालों के साथ कृषकों और पशुपालकों के हितों को भी फायदा हुआ है। पहले जहाँ उन्हें अपने उपज को औने–पौने दाम में गांव आने वाले व्यापारियों को बेचना पड़ता था, वहीं अब गांव के छोटे किसान भी अपनी उपज के अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए फसल और सब्जी मंडियों तक आसानी से पहुँच रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रबलता के साथ कार्य कर रही है कि गांवों के विकास से ही विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है और तभी विकसित भारत के सपने को भी साकार किया जा सकता है। सरकार गठन के तुरंत पश्चात् मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रदेश में पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को 500 करोड़ रुपये का आवंटन तत्काल प्रभाव से किया गया। इसकी वजह से स्वयं सहायता समूहों ने अपने सदस्यों के साथ–साथ पूरे गाँव के उत्थान के कार्यों को पुन:प्रारम्भ कर दिया। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किये जाने वाले रोजगार के कार्यों को वर्गीकृत कर सदस्यों को उन कार्यों में बेहतर दक्षता हासिल करने के लिए सरकार के द्वारा व्यापक पैमाने पर गांव–गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिससे उन सहायता समूहों के आय में भी वृद्धि संभव हुई।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में स्त्री शक्ति की भूमिका को सशक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत मई 2020 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किया। ग्रामीण महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण हेतु सखी योजना के तहत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से असमर्थ ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया गया है तथा इनके माध्यम से ही प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाओं के विकास और जन–जन तक पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इस योजना

देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले उत्तर प्रदेश के वीर सपूतों के गांव को सवांरने का जिम्मा वर्तमान योगी सरकार ने उठाया है और इसके लिए सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का संचालन 2018 से ही किया जा रहा है।

के शुरुआती चरण में ही 58000 गरीब महिलाओं को 4000 रुपये मासिक भत्ते पर बैंक सखी के पद पर नियोजित किया गया है। साथ ही इन नियोजित बैंक द्वारा सखियों के माध्यम से होने वाले प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कमीशन की भी व्यवस्था की गई है।

इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अपने आप में अनूठा और अत्यंत ही लोकप्रिय योजना **उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना** का संचालन कर रही है। इसके संचालन में सरकार और नागरिकों के बराबर की भूमिका सुनिश्चित की गयी है। वैसे लोग जो रोजगार या अन्य कारणों से गांव से बाहर शहरों या विदेशों में जाकर रह रहे हों और अपने गांव के विकास के लिये कुछ करना चाहते हों, किसी प्रोजेक्ट को स्थापित करना चाहते हों तो सरकार इसमें उनकी मदद करेगी और उनके प्रोजेक्ट पर आने वाले कुल खर्च का 50 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत गांव में सामुदायिक भवनों का निर्माण,खेल स्टेडियमों का निर्माण,व्यायामशाला,कौशल विकास केंद्रों के निर्माण के साथ-साथ सीसीटीवी निगरानी केंद्र, सीवरेज सिस्टम,सोलर प्लांट, सोलर लाइटों से गांव को सुसज्जित कराने का काम भी किया जा सकता है।

देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले उत्तर प्रदेश के वीर सपूतों के गांव को सवांरने का जिम्मा वर्तमान योगी सरकार ने उठाया है और इसके लिए सरकार की ओर से **उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना** का संचालन 2018 से ही किया जा रहा है। इस योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया कि शहीद होने वाले वीर सपूतों के गांव को शहीद ग्राम के नाम से जाना जाएगा। उनकी वीर गाथा ग्रामवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बने, इसलिए उनके याद में गांव में शहीदों की मूर्ति स्थापित की जाएगी तथा उनके नाम से गांव में प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। साथ ही उन गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण, बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा तथा माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज और महाविद्यालयों की भी शुरुआत की जाएगी। विगत तीन वर्षों में सैंकड़ों गांवों का कायापलट इस योजना के तहत हो चुका है और शहीदों के सम्मान में बनी ये योजना आज पूरे देश भर में विकास के नये नजरिये का प्रतीक बन चुकी है।

योगी जी के नेतृत्व में चलायी जा रही ग्रामीण विकास की योजनाओं की कड़ी में मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के जिक्र बिना पूरी बात ही अधूरी रह जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण इलाकों में तेईस लाख पक्के घरों का निर्माण करवा कर बेघरों को छत प्रदान किया जा चुका है। ये आंकड़ा पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक है। ये मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्रामीण विकास के लिए सार्थक प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए वो अपने आप में कम ही साबित होगी। और यही वजह है कि योगी दोबारा सरकार बनाने में सफल रहे।

◆◆◆

#InvestForGood

Invest with us to help build a better world for yourself and for those around you. Because good spreads good.
Download the DSP Mutual Fund App today!

SCAN TO DOWNLOAD

DSP MUTUAL FUND

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

अभ्युदय वात्सल्यम् वीमेन अचीवर्स अवॉर्ड में पधारे अतिथि गण : बाएँ से - अभय तिवारी (एमडी एवं सीईओ, एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस), नवनीत मुनोट (एमडी एवं सीईओ, ग्रुप), पद्मभूषण रज्जूभाई श्रॉफ (चेयरमैन, यूपीएल लिमिटेड), कृपाशंकर तिवारी (संस्थापक सम्पादक, अभ्युदय वात्सल्यम्), शरद माथुर (एमडी एवं सीईओ, यूनिवर्सल सोम्पो

अभ्युदय वात्सल्यम्
वीमेन अचीवर्स अवॉर्ड
में सम्मानित हुईं दिग्गज महिलाएँ

> **"अभ्युदय वात्सल्यम् समाचार पत्रिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई के उद्योग, राजनीति, प्रशासन, पत्रकारिता, चिकित्सा एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों ने शिरकत किया।**

अभ्युदय वात्सल्यम् पत्रिका द्वारा 5 अप्रैल, 2022 को मुंबई स्थित होटल आईटीसी ग्रैंड सेन्ट्रल में वीमेन अचीवर्स अवॉर्ड का आयोजन किया गया, जिसमें यूपीएल लिमिटेड के चेयरमैन पद्मभूषण रज्जूभाई श्रॉफ बतौर मुख्य अतिथि तथा हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ नवनीत मुनोट, एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस के एमडी – सीईओ अभय तिवारी, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ शरद माथुर एवं सनफ्रान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष मिश्रा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

अभ्युदय वात्सल्यम् पत्रिका द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन नीरजा बिड़ला को चेंजमेकर ऑफ द ईयर, एडेलगिव फाउंडेशन की चेयरपर्सन विद्या शाह को एक्सेम्पलरी वुमन ऑफ द ईयर, सुप्रसिध्द शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉ. सोमा घोष को बेस्ट क्लासिकल सिंगर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर को बेस्ट वुमन पॉलिटिशियन, मुंबई उपनगर की आईएएस कलेक्टर निधि चौधरी को बेस्ट ब्यूरोक्रैट, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा शाह को आउटस्टैंडिंग हेल्थकेयर लीडर ऑफ द ईयर,

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड), निरंजन हीरानंदानी (मैनेजिंग डायरेक्टर, हीरानंदानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), संतोष मिश्रा (मैनेजिंग डायरेक्टर, सन्फ्रान ग्रुप)

शिलपुत्सी इण्डिया की सीईओ पूर्वी शेठ को बेस्ट एचआर स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द ईयर, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पॉवर सोल्यूशन्स लिमिटेड की सीईओ सुलज्जा फ़िरोदिआ को बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर, सीए भावना दोशी को फाइनेंसियल लीडर ऑफ द ईयर, एडवोकेट आभा सिंह को सोशल रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा को एक्सेम्पलरी वुमन आंत्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर, द एकेडमी स्कूल की सीईओ डॉ. मैथिली ताम्बे को बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर, नवभारत टाइम्स की बिजनेस एडिटर सुधा श्रीमाली को नेशन बिल्डिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, आरव ग्रुप की सीईओ रीना तिवारी को इमर्जिंग आईटी लीडर ऑफ द ईयर, जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की डीन डॉ. पल्लवी सापले को कोरोना वारियर और कारुलकर प्रतिष्ठान की वाइस चेयरपर्सन शीतल कारुलकर को एक्सेम्पलरी वुमन इन ह्यूमन वेलफेयर का अवॉर्ड दिया गया।

इस मौके पर अभ्युदय वात्सल्यम् पत्रिका के संस्थापक संपादक कृपाशंकर तिवारी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किया। पत्रिका के प्रधान संपादक आलोक रंजन तिवारी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिलायें आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं और वे तमाम क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं।

आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की फाउंडर एवं चेयरपर्सन नीरजा बिड़ला का अवॉर्ड उनकी सबसे छोटी बेटी अद्वैतेषा बिड़ला ने प्राप्त किया, जो उजास नामक एनजीओ की फाउंडर हैं और वह मेंस्टुअल हाइजीन एवं महिला कल्याण से जुड़े तमाम मुद्दों पर जमीनी स्तर पर काफी काम कर रही हैं। अभ्युदय वात्सल्यम् द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई के उद्योग, राजनीति, प्रशासन, पत्रकारिता, चिकित्सा एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों ने शिरकत किया।

दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी एवं यूपीएल लिमिटेड के चेयरमैन पद्मभूषण रज्जूभाई श्रॉफ

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं यूपीएल लिमिटेड के चेयरमैन पद्मभूषण रज्जूभाई श्रॉफ

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि एवं हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी

नवनीत मुनोट एवं निरंजन हीरानंदानी आपस में बातचीत करते हुए

सुश्री अद्वैतेषा बिड़ला का अभिवादन करते हुए हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी

सम्मान समारोह में अपने विचार साझा करती हुईं सम्मानमूर्ति सीए भावना दोशी

समारोह को सम्बोधित करते हुए अभ्युदय वात्सल्यम् के संस्थापक सम्पादक कृपाशंकर तिवारी

समारोह को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि एवं एसयूडी लाइफ के एमडी-सीईओ अभय तिवारी

सम्मान समारोह में अपने विचार साझा करती हुईं सम्मानमूर्ति पूरवी शेठ, सीईओ, शिल्पुत्सी इंडिया

समारोह को सम्बोधित करते हुए अभ्युदय वात्सल्यम् के प्रधान सम्पादक आलोक रंजन तिवारी

सम्मान समारोह में अपने विचार साझा करती हुईं सम्मानमूर्ति सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि एवं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी-सीईओ नवनीत मुनोट

समारोह के विशिष्ट अतिथि नवनीत मुनोट का स्वागत करते हुए अभ्युदय वात्सल्यम् के संस्थापक कृपाशंकर तिवारी

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि एवं यूनिवर्सल सोम्पो जीआईसी के एमडी-सीईओ शरद माथुर

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संतोष मिश्रा का सम्मान करते हुए पूर्व आईआरएस के.एस. मिश्रा

कार्यक्रम समापन के बाद तस्वीर खिंचाती सम्मानमूर्ति एड. आभा सिंह, सुधा श्रीमाली एवं डॉ. पल्लवी सापले

चेंजमेकर ऑफ द ईयर

नीरजा बिड़ला

संस्थापक एवं चेयरपर्सन, आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट

आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की फाउंडर एवं चेयरपर्सन श्रीमती नीरजा बिड़ला का सम्मान प्राप्त करती हुईं उनकी सबसे छोटी बेटी अद्वैतेषा बिड़ला

आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन श्रीमती नीरजा बिडला, शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त व्यक्तित्व की परिचायक हैं। आपने आदित्य बिडला वर्ल्ड एकेडमी की स्थापना की है जो भारतीयता के मूल्यों पर आधारित अपनी तरह का अनोखा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है। श्रीमती नीरजा बिड़ला मानसिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण बदलने पर केंद्रित एक आंदोलन की स्थापना की है। श्रीमती बिड़ला द्वारा संचालित इस कल्याणकारी कदम का नाम है– एम पावर, जो भारतीय समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण मानसिक देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित है। बोधगम्य तरीके से मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बदेना ही एम पॉवर का प्रमुख उद्देश्य है।

एम पॉवर का मिशन व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा कर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों को सशक्त बनाना, रोकथाम की वकालत करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और विश्व स्तरीय समग्र सेवाएं प्रदान करना है, ताकि वे सम्मान के साथ सार्थक और रचनात्मक जीवन जी सकें। श्रीमती बिड़ला का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रभावित लोगों के बारे में जागरूकता और समर्थन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर कोई एक सुखी और स्वस्थ जीवन का हकदार है और एम पॉवर इसी दिशा में निरंतर अग्रसर है। समग्र शिक्षा आधार को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के क्रम में, श्रीमती बिड़ला ने आदित्य बिड़ला शिक्षा अकादमी की स्थापना की है, जिसके माध्यम से यंग माइंडस को पोषित करने वाले प्रतिभाशाली और समर्पित शिक्षकों की आकांक्षाओं को संवारने का शानदार प्रयास किया जाता है।

बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर

सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी

सीईओ, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पॉवर सोल्यूशन्स लिमिटेड

चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यह मान लिया जाता है कि महिलाएँ पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकतीं। इस मिथक को तोडऩे के लिए कुछ मिसालें देनी पडती हैं और काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पॉवर सोल्यूशन्स लिमिटेड की सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी की सफल औद्योगिक यात्रा ऐसी ही एक मिसाल है। व्यवसाय की दुनिया में अनेक कीर्तिमान गकी मिसाल, कंपनी तैयार करने, उसे आगे बढ़ाने और हजारों लोगों के लिए आर्थिक अवसर तैयार करने की मिसाल।

आज इनकी कंपनी के बनाए हुए इंजन को नीदरलैंड की टोमोज, इटली की अगस्ता के अलावा भारत में फोर्ड, टाटा मोटर्स, करारो, विस्टोन जैसी कंपनियां खरीद रही हैं। इसके अलावा काइनेटिक ने कई अन्य कंपनियों से व्यापारिक साझेदारी भी की है। इन्होंने बेल्जियम के इकारोस सोलर ग्रुप के साथ मिलकर इकारोस काइनेटिक सोलर नामक कंपनी की स्थापना की है जो कम क्षमता वाले ऊर्जा समाधान उपलब्ध करवाती है। सुलज्जा मोटवानी ने अपने कौशल से यह साबित कर दिया कि अगर अवसर मिले तो महिलाएँ कमाल करने से नहीं चूकती हैं। आज काइनेटिक का इतना विस्तार इनके बेजोड़ नेतृत्व कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और उसे लागू करने के लिए भरपूर श्रम से ही फलीभूत हो सका है। सुलज्जा के कार्यकाल में काइनेटिक समूह ने जबरदस्त विस्तार देखा।

सोशल रिफॉर्मर ऑफ द ईयर

एडवोकेट आभा सिंह

सुप्रसिद्ध वकील एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता

एडवोकेट आभा सिंह देश की उन चुनिंदा और प्रभावशाली वकीलों में से एक हैं जिन्होंने अपनी पेशेवर सुयोग्यता के माध्यम से विधि के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है। आज एडवोकेट आभा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एडवोकेट आभा सिंह के नाम से भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात आभा सिंह ने अनगिनत लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान कर उनके हक की लड़ाई लड़ी है। एडवोकेट आभा सिंह भारतीय डाक सेवा में निदेशक के पद पर तैनात थीं और टॉप क्लास नौकरी छोड़कर वकालत के पेशे में आ गईं। जब तक आभा सिंह डाक विभाग में सीनियर ब्यूरोक्रेट के रूप में तैनात थीं, इन्होंने अपने कामकाज से सिस्टम में कई आमूलचूल परिवर्तन किए। बाद में इस ठाट – बाट वाली सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर समाज सेवा के क्षेत्र में आ गईं और आज एडवोकेट आभा सिंह वकालत के माध्यम से कमजोरों और बेजुबानों की आवाज बनीं हुई हैं। आप हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ पैरवी भी कर चुकी हैं और इसके अलावा आभा सिंह कोलंबिया समेत तमाम देशों में व्याख्यान के लिए आमंत्रित में की जाती रही हैं। एडवोकेट आभा सिंह ने स्त्री दशा और दिशा नामक किताब भी लिखी है, जो महिला अधिकारों पर केंद्रित है। इस किताब के विमोचन के दौरान मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री, गुलपनाग और अन्य सेलेब्रिटीज ने आभा सिंह के लेखन की काफी सराहना की थी।

आउटस्टैंडिंग हेल्थकेयर लीडर ऑफ द ईयर

श्रीमती अमीरा शाह

मैनेजिंग डायरेक्टर, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती अमीरा शाह की ओर से उनका अवार्ड प्राप्त करते हुए कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्री राकेश अग्रवाल

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती अमीरा शाह की गिनती देश की सफल महिला उद्यमियों में होती है। एक ऐसी उद्यमी जिन्होंने न केवल अपने पारिवारिक व्यवसाय में रुचि ली बल्कि उसे एक नई ऊँचाई पर ले गई। जोखिम भरे और अनिश्चित व्यवसाय प्रारूपों में ऐसे उदाहरण बाजार को प्रेरित करने वाले होते हैं। 22 साल की उम्र में जब कई युवा अपनी जिन्दगी के फैसलों को लेकर बहुत भ्रमित होते हैं, उस उम्र में अमीरा शाह ने अपने पिता द्वारा स्थापित व्यवसाय को संभालने का निर्णय लेकर अपने मजबूत इरादों का परिचय दिया। टेक्सास में नौकरी छोड़कर कुछ सृजनात्मक करने और जीवन सार्थक बनाने के उद्देश्य से अमीरा ने भारत आकर पिता की डायग्नोस्टिक लैब संभाली और अपने मेहनत के दम पर देखते ही देखते उन्होंने सिंगल लैबोरेटरी को हजारों करोड़ के एम्पायर में तब्दील कर दिया।

मेट्रोपोलिस आज एक सम्मानित हेल्थकेयर ब्रांड बन गया है, जिसकी लैबोरेटरीज में सालाना 30 मिलियन से अधिक टेस्ट होते हैं। वित्तीय मोर्चे पर, मेट्रोपोलिस ने वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 17 % की वृद्धि हासिल की और पिछले वित्तीय वर्ष 20–21 में 998 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया। कंपनी ने 19 मिलियन परीक्षण किए और लगभग 10 मिलियन रोगियों का उपचार किया। इस महामारी के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन से व्यवसाय संचालन में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस कठिन समय में डायग्नोस्टिक्स में प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से एक होने के नाते इन्होंने सुनिश्चित किया था कि इनकी टीम कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार रहे।

एक्सेम्पलरी वुमन ऑफ द् ईयर

विद्या शाह

चेयरपर्सन, एडेलगिव फाउंडेशन

श्रीमति विद्या शाह, एडेलगिव फाउंडेशन श्रीमती विद्या शाह, एडलगिव फाउंडेशन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एडेलगिव फाउंडेशन अनुदान देने वाला एक गैर सरकारी संगठन है, जो कमजोर बच्चों, महिलाओं और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध छोटे एवं मध्यम आकार वाले जमीनी स्तर के एनजीओ के विकास और समर्थन के द्वारा भारत में परोपकार के सृजन और विस्तार में मदद करता है। पिछले 13 वर्षों में, एडेलगिव ने भारत के 14 राज्यों के 111 जिलों में 150 से अधिक संगठनों को सहयोग प्रदान किया है, जिससे परोपकार 4.1 बिलियन रुपये से अधिक की प्रतिबद्धताओं को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जा सका। एडेलगिव फाउंडेशन उन संगठनों के साथ काम करता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और विभिन्न समुदायों के लिए सुलभ आजीविका के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

श्रीमती विद्या शाह वित्तीय क्षेत्र की बड़ी कंपनी एडलवइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं और इसके अलावा आप कई निवेश सलाहकार फर्मों जैसे मबेला ट्रस्टी सर्विसेज और स्पायर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बोर्ड में निदेशक रूप में भी काम करती हैं। विद्या जनाग्रह, एशियन वेंचर फिलैंथ्रोपी नेटवर्क, मासूम, अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन जैसे कई संगठनों को भी सहयोग प्रदान करती हैं। आप सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी और मनदेशी फाउंडेशन जैसे संगठनों के सलाहकार परिषद में भी हैं।

बेस्ट क्लासिकल सिंगर ऑफ द् ईयर

पद्मश्री डॉ. सोमा घोष

सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका

पद्मश्री डॉ. सोमा घोष देश की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और मशहूर शहनाई वादक एवं भारत रत्न स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मानस पुत्री हैं। पद्मश्री सोमा घोष की माँ संगीत की शिक्षिका और कवियत्री थीं। इस कारण मां के गर्भ में ही सोमा घोष ने संगीत सुनना शुरू कर दिया था। इस तरह, आपकी मां ने आपके जन्म से से पहले ही आपको संगीत से परिचित करा दिया था।

बनारस में आपका संयुक्त परिवार था, आपकी मां को कई लोगों की देखभाल और घर के बहुत सारे कामकाज करने पड़ते थे। फिर भी, उन्होंने अपनी कलात्मक गतिविधियों को कभी नहीं छोड़ा और आपके माध्यम से इस परिपाटी में आगे बढ़ाया। अपनी मां से शास्त्रीय संगीत सीखने वाली डॉ. सोमा घोष बागेश्वरी देवी को अपनी गुरु मानती हैं।

अपने गुरु और अपनी मां के गुरु भाई सेनिया घराने के गायक नारायण चक्रवर्ती के कहने पर सोमा घोष बागेश्वरी देवी के पास ठुमरी सीखने गई। नारायण चक्रवर्ती ने ही आपको ठुमरी गाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि सोमा घोष का गला ठुमरी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। डॉ. घोष पहली ऐसी भारतीय गायिका हैं जिन्हें संसद भवन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिल चुका है और भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया है।

बेस्ट ब्यूरोक्रैट ऑफ द ईयर

निधि चौधरी (आईएएस)

कलेक्टर, मुंबई उपनगर

श्रीमती निधि चौधरी महाराष्ट्र कैडर की 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में आप मुंबई उपनगर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर हैं। आप एक युवा प्रेरक व्यक्तित्व हैं और कार्य के प्रति अपने जुनून के कारण काफी लोकप्रिय हैं । दायित्वों के ईमानदार निर्वहन और नैतिक प्रशासन के लिए आप विख्यात हैं। आप मुंबई में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की उप सचिव रह चुकी हैं। आप रायगढ़ में कलेक्टर के रूप में अपना योगदान दे चुकी हैं। आपकी सफलता की कहानी भी काफी प्रेरक है। श्रीमती चौधरी एक साधारण परिवार से हैं और आपके सिंबलिंग्स ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास की है। सिविल सेवा में आने के पहले आप आरबीआई में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं । आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन और अंग्रेजी से परास्नातक किया है। इसके साथ ही श्रीमती चौधरी ने यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और फिर 2011 में सिविल सेवा के लिये चुनी गईं।

एक्सेम्पलरी वुमन इन ह्यूमन वेलफेयर

शीतल कारुलकर

वाइस - चेयरपर्सन, कारुलकर प्रतिष्ठान

श्रीमती शीतल कारुलकर, कारुलकर प्रतिष्ठान की वाइस – चेयरपर्सन हैं। इसके साथ ही आप केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में हैं तथा वर्ल्ड कम्युनिकेशन फोरम एसोसिएशन की कॉर्पोरेट सदस्य हैं और बीमा पाठशाला की महिला विंग की प्रमुख हैं। श्रीमती कारुलकर समाज की बेहतरी और वंचित उत्थान के लिये लगातार सक्रिय हैं। आप अपनी महान दादी सास श्रीमती कमलाबाई तुकाराम कारुलकर की विरासत को आगे बढ़ा रहीं हैं। श्रीमती कमलाबाई ने ही 1969 में इस प्रतिष्ठान की स्थापना की थी। आपने बायो केमिस्ट्री में डिग्री हासिल की और 21 साल की उम्र में एक फार्मास्युटिकल कंपनी के साथ अपना कैरियर शुरू किया।

आपका इस दर्शन में अटूट विश्वास है कि एक स्पष्ट दृष्टि से मील का पत्थर देखा जा सकता है और एक सही रास्ता आपको वहाँ पहुंचाएगा। इस दर्शन में विश्वास की भावना ने आपको अनेक क्षेत्रों में सफलता दिलाई है। आपको कर्मयोद्धा ग्रंथ के लोकार्पण के अवसर पर भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त आपको दिल्ली के विज्ञान भवन में उप राष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू जी की उपस्थिति में आरएसएस के सरसंघचालक श्री मोहनजी भागवत द्वारा सम्मानित किया गया। स्वनाथ फाउंडेशन के शुभारंभ के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। आप 100 से भी अधिक लडकियों की शिक्षा की व्यवस्था कर रहीं हैं। साथ ही आप पालघर लिंचिंग की घटना के शिकार परिवार की बुनियादी खर्चे और शिक्षा व्यय का भार उठा रही हैं। आपके नेतृत्व में हर साल कारुलकर प्रतिष्ठान की टीम द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम चलाया जाता है।

बेस्ट पॉलिटीशियन ऑफ द् ईयर

श्रीमती रुपाली चाकणकर

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

श्रीमती रुपाली चाकणकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। श्रीमती चाकणकर की समाजसेवी एवं जनसेवी गतिविधियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया।

मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे जिला से ताल्लुक रखने वाली रुपाली चाकणकर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। रूपाली की सासू माँ श्रीमती रुक्मिणी चाकणकर थायरी गांव की नगर पालिका की पहली पार्षद थीं। सासू माँ की राजनीतिक गतिविधियों ने श्रीमती रुपाली चाकणकर को राजनीति के क्षेत्र आने के लिए प्रेरित किया।

रूपाली चाकणकर के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से पुणे जिले में जरूरतमंद लोगों को 10,000 साइकिल दान किया गया था। श्रीमती रुपाली चाकणकर पर्यावरण को लेकर काफी सजग रहती हैं और इसी का परिणाम है कि झीलों को बचाने के लिए आप सेव द लेक नामक अभियान भी चलाती हैं।

आपको सामाजिक जीवन में विशिष्ट योगदान के लिए तमाम सम्मान प्राप्त हैं। स्वभाव से हमेशा सहज रहने वाली रूपाली चाकणकर महिलाओं की सुरक्षा एवं प्रगति के मुद्दे पर काफी सक्रिय रहती हैं ।

कोरोना वारियर

डॉ . पल्लवी सापले

डीन, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स

डॉ. पल्लवी सापले, महाराष्ट्र सरकार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की डीन हैं। बाल रोग में विशेषज्ञ की योग्यता रखने वाली डॉक्टर पल्लवी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का कई बार लोहा मनवाया है। सरकार ने कोरोना का प्रसार ग्रामीण इलाकों में रोकने के लिए इन्हें ग्रामीण भाग में भेज दिया था। जहां , सफलतापूर्वक इन्होंने 6 बेड के आईसीयू को 106 बेड तक पहुंचा दिया। कॉलेज खुलने के 30 साल बाद पहली बार, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करवाकर इलाके में सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध कराई। कोरोना की दूसरी लहर में जब पूरे देश में मौत के समाचार ने सभी को झकझोर दिया था, उस समय भी मृत्यु दर को सबसे अधिक नियंत्रित करने में धुले मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र में सबसे अलग रहा। देश के आजाद होने के बाद वे जेजे की सबसे युवा डीन बनी। समस्याओं को समझना और उनका बारीकी से हल निकालने की बेहतरीन कला के माध्यम से इन्होंने मरीजों और मेडिकल स्टूडेंट्स की कई जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया है। प्राइवेट सेक्टर में काम के कई मौके होने के बावजूद डॉ. पल्लवी ने अंतिम व्यक्ति को सेवा देने के लक्ष्य के साथ सरकारी व्यवस्था में ही रहना बेहतर समझा। खाने – पीने की बेहद शौकीन पल्लवी, स्वभाव से बेहद विनम्र हैं और आसानी से उपलब्ध रहती हैं ।

एक्सेम्पलरी वुमन आंत्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर

अमीषा वोरा

जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रभुदास लीलाधर ग्रुप

श्रीमती अमीषा वोरा प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रमुख शेयरहोल्डर हैं। श्रीमती वोरा भारत की अग्रणी महिला उद्यमियों में से एक हैं। 1987 में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद, अमीषा वोरा ने जेएम फाइनेंशियल के साथ एक विश्लेषक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी।

सामान्य पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, अमीषा वोरा ने अपनी क्षमता, पात्रता एवं सुयोग्यता के माध्यम से राष्ट्रीय औद्योगिक जगत में विशिष्ट पहचान बनाई है। आज आप भारतीय पूँजी बाजार की एक ऐसी महिला उद्यमी हैं, जिनकी कार्यकुशलता की तारीफ हर कोई करता है। वर्ष 2000 में प्रभुदास लीलाधर में शामिल होने के बाद, आपने छह साल की छोटी अवधि में ही कंपनी के संस्थागत व्यवसाय को 36 गुना बदिया। बैंकिंग और पॉवर इक्विपमेंट पर आधारित आपके अभिनव कॉन्फ्रेंसेस के परिणामस्वरूप ऐसे शेयरों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई।

श्रीमती अमीषा वोरा ने अपनी इस शानदार औद्योगिक यात्रा में कॉर्पोरेट सलाहकार व्यवसाय का कुशल नेतृत्व किया है और 2005-08 के दौरान तमाम कॉर्पोरेट्स को 1.8 बिलियन डॉलर जुटाने में मदद की। आपके सुयोग्य नेतृत्व में, कंपनी ने 2006 में अपना एनबीएफसी व्यवसाय शुरू किया और बाद में 2007 में पी.एल. कैपिटल मार्केट्स प्रा. लि. के माध्यम से निवेश बैंकिंग व्यवसाय की भी शुरूआत हुई। अमीषा वोरा ने 2012 में प्रभुदास ग्रुप के रिटेल डिवीजन का कार्यभार संभाला और तब से, प्रमुख बाजारों में कंपनी की व्यावसायिक उपस्थिति को मजबूत किया और सलाहकार सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि भी सुनिश्चित की।

नेशन बिल्डिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर

सुधा श्रीमाली

बिजनेस एडिटर, नवभारत टाइम्स, मुंबई

श्रीमती सुधा श्रीमाली पिछले 18 सालों से नवभारत टाइम्स, मुंबई में बतौर बिजनेस एडिटर कार्यरत हैं। समाचार पत्रों में विभिन्न लेखों के माध्यम से आम लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता और जागरूकता फैलाना ही सुधा श्रीमाली के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। आपने शेयर मार्केट गाइड नामक पुस्तक भी लिखी है जो प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई है। आपने टाइम्स ग्रुप के माध्यम से वित्तीय विषयों पर आधारित कई कार्यशालाओं, सेमिनारों, साक्षात्कारों और फेसबुक लाइव में समन्वयक और मॉडरेटर की शानदार भूमिका का निर्वहन किया है। 2018 में अमेरिकी सरकार द्वारा आपको महिला उद्यमिता शिखर सम्मलेन में आमंत्रित किया गया था। मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखने वाली सुधा श्रीमाली अत्यंत ही विनम्र एवं सरल व्यक्तित्व की परिचायक हैं। आप मुंबई के उद्योग जगत को बहुत करीब से जानती और समझती हैं।

बेस्ट एचआर स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द ईयर

पूर्वी सेठ

सीईओ, शिलपुत्सी कंसल्टेंट

पूर्वी सेठ देश की प्रमुख एडवायजरी फर्म शिलपुत्सी कंसल्टेंट की सीईओ हैं। पूर्वी दूसरी पीढ़ी की प्रमुख उद्यमी और कुशल नेतृत्वकर्ता हैं जो शिलपुत्सी कंसल्टेंट फर्म की समग्र व्यावसायिक वृद्धि एवं दीर्घकालिक विकास की जिम्मेदारी संभालती हैं। आप विगत 25 से अधिक वर्षों से इस फर्म से जुडी हुई हैं और मुंबई, भारत में रहती है। आप एक विशेषज्ञ सलाहकार और कई प्रतिष्ठित कंपनियों, बोर्डों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की प्रमुख परामर्शदाता है।

आपके प्रस्ताव व्यवसाय को बड़े पैमाने पर स्थापित करने, जटिल रणनीतिक परियोजनाओं के क्रियान्वन हेतु समूहों का मार्गदर्शन करने, मानव संसाधन और बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग कर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए हैं। आप एक विचारशील एवं प्रगतिशील नेतृत्वकर्ता हैं।

आप अपने अभिनव विचारों एवं प्रभावी समाधानों से मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग कर व्यावसायिक अवसरों की उपलब्धता और अधिकतम प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित कराती हैं। इसके अतिरिक्त आपके हिस्से कुछ ऐसी उपलब्धियाँ भी रहीं हैं जो आपके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को दर्शाती है। आपको 27 साल की उम्र में सबसे युवा सीनियर कंसल्टेंट होने का गौरव प्राप्त है। साथ ही बिजनेस टुडे के इंडियाज अंडर 40 को जज करने के लिए लगातार आठ साल जूरी पैनल के आप सबसे युवा सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त आप आईआईटी, मुंबई और खड़गपुर में उद्यमिता सेल के सलाहकार और मेंटर की भूमिका में है।

फाइनेंसियल लीडर ऑफ द ईयर

सीए भावना दोशी

संस्थापक पार्टनर, भावना दोशी एसोसिएटम एलएलपी

सीए भावना दोशी एसोसिएट्स एलएलपी की संस्थापक पार्टनर है। आपको कराधान और कॉर्पोरेट पुनर्गठन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है और आप 30 से अधिक वर्षों से राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को मलाहकार सेवाएं प्रदान कर रही है। आप एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है और आपने मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। सीए भावना दोशी इंडसइंड बैंक, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सनफार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी लिमिटेड, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केपी आईटी टेक्नोलॉ जीज लिमिटेड, ग्रेटशिप इंडिया लिमिटेड और अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों की बोर्ड मेंबर हैं आपको भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद के लिए तीन - तीन साल के चार कार्यकाल के लिए चुना गया था। आपने लेखा मानक बोर्ड, अनुसंधान, विजन 2021 और आईसीएआई की अन्य समितियों की अध्यक्षता की है। आप डॉ. पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार आयोग का समर्थन करने वाले एक समूह की सदस्य भी रहीं हैं। भावना जी के परिचय में इसका उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि आपने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा स्थापित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही आप न्यूयार्क स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सलाहकार पैनल की सदस्य भी रहीं हैं।

बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर

डॉ . मैथिली तांबे

सीईओ, द् एकेडमी स्कूल

डॉ. मैथिली तांबे, **द् एकेडमी स्कूल** की सीईओ हैं। द् एकेडमी स्कूल की स्थापना 2015 में पुणे में ग्रामोदय ट्रस्ट द्वारा महाराष्ट्र में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। टीएएस शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबी विरासत और अनुभव का सुपरिणाम है। ग्रामोदय ट्रस्ट एसएमबीटी और अमृतवाहिनी एजुकेशनल ट्रस्ट का सिस्टर ट्रस्ट है। यह पुणे के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में से एक है। दुनिया तेजी से बढ़ रही है, बच्चों की स्कूली शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, और टीएएस खुशी के साथ पढ़ाई में विश्वास करता है।

डॉ. मैथिली ताम्बे के सुयोग्य नेतृत्व में **द् एकेडमी स्कूल** छात्रों को गैर परंपरागत, नवीन और प्रगतिशील शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा में विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान कर रहा है। पेशेवर रूप से डॉक्टर रहीं मैथिली ताम्बे, शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर द एकेडमिक स्कूल के बच्चों ने एक अनूठा और अभिनव प्रयोग किया। बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की। विशेष रूप से, यह स्कूल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पुणे का पहला स्कूल बन गया है। स्कूल ने फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली की मदद से यह संभव कर दिखाया। द् एकेडमी स्कूल ने पिछले साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम करना शुरू किया था।

◆◆◆

समस्त महाजन

बेजुबान प्राणियों का स्वजन

Trust Regd. No. E/15474 (Ahmedabad)

समस्त महाजन, ३०७, राजशीला बिल्डिंग, ५९७, जे. एस. एस. रोड, चीरा बाजार, मुंबई - ४०० ००२. ☎ २२०६ ०३९० ✆ ९८२०० २०९७६

samastmahajan9@gmail.com www.samastmahajan.org

samast.mahajan samastmahajan goo.gl/wxNnQG

जीवदया योजना

मूक जीवों को राहत पहुँचाने, पशुओं को गोद लेने, गौशाला/पांजरापोलों के मददगार बनने के साथ-साथ सभी जीवों के कल्याण में भागीदार बनें।

क्र. संख्या	योजना	योगदान
१	गौशाला/पांजरापोल में शेड/गोडाउन का निर्माण	२५ लाख रुपये
२	हवाड़ा/गमान का निर्माण	२ लाख रुपये
३	एक ट्रक घास-चारा	२० हजार रुपये
४	एक पशु को एक वर्ष के लिए गोद लेना	१२ हजार रुपये

ग्रामोद्धार योजना

देश के साढ़े छह लाख गाँवों के विकास हेतु गोचरभूमि की व्यवस्था, वर्षाजल का संग्रहण तथा देशी वृक्षों का वृक्षारोपण आवश्यक है। गोचरभूमि को विकसित करने, वर्षाजल का संग्रह करने, तालाबों-नहरों आदि का पुनरुद्धार करके खेतों की पथरीली भूमि को उर्वर बनाने जैसे कार्य जरूरी हैं। गावों में बरगद, पीपल, आम, इमली, नीम, हरडे, बहेड़ा, आँवला, शमी, बेल, गूलड़, जामुन, करंज, बकुल, अर्जुन आदि वृक्षों को लगाना आवश्यक है। ग्रामोद्धार की इस पावन योजना को अमल में लाने के लिए एक गाँव के लिए १० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

क्र. संख्या	योजना	योगदान
१	एक गाँव में जल-संचय, वृक्षारोपण तथा गोचरभूमि की स्वच्छता के लिए स्वीकृत राशि	१० लाख रुपये

गोचर, तालाब, देशी वृक्ष आदि मूक जावों के लिए जीवनाधार हैं।

दानवीरों से इस सुकृत का लाभ लेने हेतु विनती

• समस्त महाजन को दिये जाने वाले दान आयकर की धारा 80(G) के अंतर्गत करमुक्ति के योग्य हैं। • समस्त महाजन को IICA (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स) में CSR NGO भागीदारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। • I A HUB code - A 000308 • BSE SAMMAAN के द्वारा मान्यता प्राप्त है। • FCRA के अंतर्गत विदेशी दान स्वीकार करने के लिए समस्त महाजन को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त है। • कृपया अपना चेक "SAMAST MAHAJAN" के नाम से लिखें।

"

व्यवसाय के साथ-साथ बाबा कल्याणी परोपकारी योजनाओं और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी खासी दिलचस्पी लेते हैं। उनका मानना है कि एक जिम्मेदार उद्योग समूह के रूप में, हमें समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और कुछ वापस करना चाहिए जिसने हमें इतना कुछ दिया है।

भारतीय उद्योग जगत के गौरव

बाबा कल्याणी

– कृपाशंकर तिवारी

भारतीय उद्योग जगत के प्रतिष्ठित और सुस्थापित व्यक्तित्व बाबा कल्याणी देश के गर्व हैं। बाबा कल्याणी भारत के ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने व्यावसायिक मूल्यों, सिद्धांतों एवं गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अपनी औद्योगिक योजनाओं को मूर्तरूप देना श्री कल्याणी का प्रथम औद्योगिक सिद्धांत है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक वह स्वाभाविक रूप से एक अंतर्मुखी किन्तु सरस, सहयोगी तथा परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं।

बाबा कल्याणी का जन्म पुणे में पेशे से इंजीनियर सुलोचना और नीलकंठ कल्याणी के घर हुआ था। उनके पिता का ऑटो पार्ट्स बनाने का एक छोटा सा कारखाना था। बाबा ने अपनी स्कूलिंग बेलगांव के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से की।

बाबा कल्याणी
चेयरमैन, भारत फोर्ज लिमिटेड

इसके बाद उन्होंने बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की। साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध एनआईटी से भी डिग्री हासिल की है। वर्तमान में वह अपने इकलौते बेटे अमित कल्याणी के साथ भारत फोर्ज का पूरा काम देख रहे हैं। आने वाले समय में बाबा का प्लान डिफेंस सेक्टर में व्यापक स्तर पर काम करना है।

फोर्ज और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान

बाबा कल्याणी देश को पहली प्राइवेट तोप (आर्टिलरी गन) यानी एडवांस टोवड आर्टिलरी गन सिस्टम देने वाले भारत फोर्ज लिमिटेड के चैयरमेन हैं।

फोर्ब्स द्वारा साल 2021 में जारी की गई इंडिया के 100 अमीरों की लिस्ट में इनका 67 वां स्थान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबा की कंपनी ने कारगिल युद्ध की हीरो रही बोफोर्स गन से ज्यादा पावरफुल और सस्ती गन (तोप) तैयार की है। इस आर्टिलरी गन को डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार किया गया। फोर्ब्स के मुताबिक, इनके पास 3.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति है।

कारगिल युद्ध में योगदान

बाबा की कंपनी का कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट करने के लिए बोफोर्स तोपों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। यह रणनीति कामयाब रही, लेकिन जल्द ही सेना के पास इन तोपों के लिए गोले खत्म होने लगे। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोफोर्स 155 एमएम होवित्जर्स के लिए शेल्स बनाने का काम बाबा कल्याणी की कंपनी भारत फोर्ज को दिया। उस दौरान कंपनी को एक लाख शेल्स का इमरजेंसी ऑर्डर मिला था, जिसे कंपनी ने कम समय में पूरा कर अपनी साख बनाई।

बाबा कल्याणी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उनकी कंपनी द्वारा तैयार 155 एमएम आर्टिलरी गन (तोप) मौजूदा बोफोर्स गन से ज्यादा पॉवरफुल है। ऑपरेशनल पैरामीटर की बात की जाए तो यह खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा मूव कर सकती है और यह 52 कैलिबर की क्षमता वाली है, जबकि बोफोर्स की क्षमता 39 कैलिबर की है। जब बाबा कल्याणी 1972 में भारत फोर्ज में शामिल हुए तब कंपनी का सालाना कारोबार 1,300,000 डॉलर था। बाद में यह भारत, अमरीका, जर्मनी, स्वीडन और चीन भर में फैले 11 विनिर्माण सुविधाओं के साथ एक वैश्विक कंपनी बन गयी। श्री कल्याणी भारत में ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट एक्सपोर्ट के पायोनीर माने जाते हैं।

बाबा कल्याणी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा निर्देशित इस समूह के पास 10,000 से अधिक मजबूत वैश्विक कार्यबल है। साथ ही यह समूह आज अपने सभी संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों में एक मार्केट लीडर के तौर पर जाना जाता है। कल्याणी समूह एक विश्वस्तरीय कंपनी है और यह अपने व्यवसाय के हर पहलू में अग्रणी बनने का प्रयास करता है। हमेशा से ही इनोवेशन समूह के लिए प्रेरक शक्ति रहा है और इसे व्यवसाय के हर पहलू पर लागू किया जाता है। नवोन्मेष की भावना कल्याणी समूह को वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाकर व्यवसायों को आक्रामक रूप से विकसित करने के लिए प्रेरित करती है।

उद्यम,परोपकार और पर्यावरण

व्यवसाय के साथ-साथ बाबा कल्याणी परोपकारी योजनाओं और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी खासी दिलचस्पी लेते हैं। इनका मानना है कि एक जिम्मेदार उद्योग समूह के रूप में, हमें समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और कुछ वापस करना चाहिए जिसने हमें इतना कुछ दिया है। इसलिए कल्याणी समूह नैतिक रूप से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने शिक्षा, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और समुदाय जैसे क्षेत्रों में कई पहलें की हैं।

समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मिले इसके लिए श्री कल्याणी कई योजनाएँ संचालित कर रहे हैं। आप प्रथम पुणे शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक हैं,जो स्थानीय समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में लगी हुई है। अपनी स्थापना के बाद से इस संस्था ने पुणे में 100,000 से अधिक बच्चों के जीवन में बदलाव लाने में सफलता पाई है। इसके अलावा एक प्रशिक्षण केंद्र भी चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं के लिए स्वतंत्र तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा श्री कल्याणी अनेक परोपकारी और धर्मार्थ संगठनों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इतना ही नहीं ये व्यवसाय के साथ-साथ पर्यावरण हितों का भी ध्यान रखते हैं। इसी संदर्भ में एक स्वच्छ और उत्सर्जन से मुक्त वातावरण हेतु योगदान करने के लिए, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए विभिन्न ऊर्जा कुशल पवन टर्बाइन का निर्माण करने के लिए Kenersys लिमिटेड की स्थापना की गई है। कंपनी की महाराष्ट्र में अपनी विंड टर्बाइन है जो हरित ऊर्जा कंपनी के उत्पादकों के कार्यों के लिए बनाई गई है। इनकी कंपनी

बाबा कल्याणी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उनकी कंपनी द्वारा तैयार 155 एमएम आर्टिलरी गन (तोप) मौजूदा बोफोर्स गन से ज्यादा पॉवरफुल है।

गैर–परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के लिए सौर ऊर्जा उपकरण को विकसित करने में लगी हुई है। केपीआईटी कमिंस के साथ एक संयुक्त उद्यम में, भारत फोर्ज अपने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

बाबा कल्याणी ने जहाँ अपने पिता से प्राप्त विरासत को शिखर पर पहुँचाया है तो वहीं कल्याणी ग्रुप के व्यापक विस्तार के लिए अपने सुपुत्र अमित कल्याणी को भी बखूबी तैयार किया है। दिलचस्प बात यह है कि कल्याणी ग्रुप के संस्थापक श्री नीलकंठ कल्याणी ने मैट्रिक तक की साधारण शिक्षा प्राप्त की थी तो वहीं बाबा कल्याणी ने एमआईटी और अमित कल्याणी ने बुकनाल यूनिवर्सिटी, यूएसए से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है।

पुरस्कार व सम्मान

कल्याणी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मभूषण प्राप्त है। यह पुरस्कार व्यापार और इंडस्ट्री में उनके शानदार योगदान के लिये मिला है। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र भूषण, ग्लोबल इकॉनमी प्राइज–2009, जर्मन बिजनेसमैन ऑफ द इयर–2006, इंटरप्रिन्योर्स ऑफ द इयर–2005 और सीईओ ऑफ 2004 के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही आप सीआईआई राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष रहे हैं तथा आपने भारत–जापान बिजनेस लीडर्स फोरम की सह–अध्यक्षता का दायित्व निभाया है। इसके अतिरिक्त श्री कल्याणी इंडो–फ्रेंच सीईओ फोरम के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा आप देश–दुनिया के प्रतिष्ठित आर्थिक मंचों और संगठनों से संबद्ध रहे हैं।

कल्याणी ग्रुप की स्थापना से जुड़े दिलचस्प तथ्य

कल्याणी ग्रुप की स्थापना की बात करें तो ग्रुप के संस्थापक नीलकंठ कल्याणी को सन् 1954 में अपने पिता के निधन के बाद पढ़ाई छोड़कर परिवार के कारोबार को सँभालना पड़ा था। अधूरी शिक्षा की क्षतिपूर्ति महाराष्ट्र के पूर्व वरिष्ठ राजनेता स्व. यशवंतराव चौहाण ने की। चौहाण को कल्याणी परिवार से बचपन में पुत्रतुल्य संरक्षण मिला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस कर्ज को उतारने के लिए नीलकंठ कल्याणी को उद्योग स्थापना के लिए प्रेरित किया और मदद की। स्वर्गीय चौहाण के सिफारिशी पत्र से नीलकंठ कल्याणी को केंद्रीय उद्योग मंत्रालय से फोर्जिंग कारखाना लगाने की अनुमति मिल गई। परिवार के ही नजदीकी मित्र शान्तनुराव लक्ष्मणराव किर्लोस्कर (किर्लोस्कर समूह) की सहायता से उन्होंने सन् 1961 में भारत फोर्ज की स्थापना की।

इस कारखाने के 15 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश में श्री नीलकंठ कल्याणी का हिस्सा मात्र 2 लाख रुपए था। पाँच–पाँच लाख रुपए किर्लोस्कर व कोल्हापुर के महाराजा ने निवेश किए थे। तीन लाख रुपए का कर्ज बैंक से मिला था। परमिट व लायसेंस राज में नया कारखाना स्थापित करना कितना कठिन काम था, इसका प्रमाण है कि स्थापना के पाँचवें वर्ष सन् 1966 में कंपनी फोर्ज शॉप स्थापित कर पाई और आठवें वर्ष में पहली फोर्जिंग बना पाई। स्वर्गीय चौहाण की सिफारिश से कारखाना लगाने की अनुमति तो मिल गई थी, पर कई अन्य औपचारिकताओं के लिए श्री नीलकंठ कल्याणी को विभिन्न मंत्रालयों में पाँच साल चक्कर लगाने पड़े।

सन् 1962 में भारत–चीन युद्ध हुआ, फलतः भारत फोर्ज को उत्पादन शुरू करने के लिए सन् 1966 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहली पीढ़ी ने अपने काल की प्रचलित व्यवस्था व अवरोधों के बीच अपने मित्रों की मदद से अपना दायित्व पूरा किया। सन् 1972 में श्री बाबा कल्याणी पिता के सहयोगी बने। उनका पहला अनुभव भी तीखा रहा। उनके ज्वॉइन करते ही कई टॉप मैनेजर्स समूह छोड़कर चले गए।

23 वर्षीय श्री बाबा कल्याणी सलाह लेने के लिए श्री किर्लोस्कर के पास पहुँचे तो गुरुमंत्र मिला कि अपना हक जूझने से मिलता है और इसका आसान उपाय है पानी में कूद पड़ो। स्व. किर्लोस्कर के इस कथन ने श्री बाबा कल्याणी का हौसला बढ़ाया।

अमित कल्याणी
उप प्रबन्ध निदेशक, भारत फोर्ज लिमिटेड

कुशल व्यावसायिक नेतृत्व के परिचायक

अमित कल्याणी

अमित की सीएसआर परियोजनाओं और परोपकार में विशेष रुचि है। वह समाज को वापस देने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं।

कुशल एवं कर्मठ नेतृत्व द्वारा किसी भी सामूहिक प्रयास को सफ़ल बनाया जा सकता है। ठीक यही बात व्यवसाय और उद्योग पर भी लागू होती है। कोई भी उद्यम उन्नति की ओर तभी अग्रसर होता है जब उसका प्रमुख अपने कुशल एवं सुयोग्य नेतृत्व के माध्यम से अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को मूर्त रूप देता है। इसी तरह भारत

फोर्ज लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक अमित कल्याणी ने भी अपने कर्मठ एवं कुशल नेतृत्व के माध्यम से कम्पनी को व्यावसायिक बुलंदियों पर पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमित का जन्म 1975 में हुआ। अकादमिक अनुभव को देखें तो अमित कल्याणी बकनेल विश्वविद्यालय, पेनसिल्वेनिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री रखते हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से स्नातक भी हैं। विनिर्माण और प्रौद्योगिकी को लेकर अमित बेहद संवेदनशील हैं और नियमित रूप से वह विश्व आर्थिक मंच, दावोस में भाग लेते हैं।

अमित व्यावसायिक रूप से अत्यंत कुशाग्र और शानदार लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। दूरदर्शी सोच, रचनात्मक क्षमता और प्रबंधन कौशल – ये सभी अमित कल्याणी के कुशल नेतृत्व के विभिन्न पहलू हैं। पिता बाबा कल्याणी के पदचिन्हों पर चलते हुए अमित ने बिजनेस की बारीकियां सीखी और कम्पनी की छोटी से लेकर बड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए समृद्ध अनुभव हासिल किया। आज अमित कल्याणी देश के उन युवा उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने कर्मठता के साथ अपने औद्योगिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

कल्याणी ग्रुप स्पेशलिटी स्टील, हाई-टेक मेटलर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ स्पेशियलिटी केमिकल्स के क्षेत्रों में काम करता है। भारत फोर्ज लिमिटेड का राजस्व 1.4 बिलियन डॉलर है, जिसकी दस विनिर्माण क्षेत्र में अंतरमहाद्वीपीय उपस्थिति है। अमित भारत फोर्ज के व्यवसाय की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं।

अमित कल्याणी पिछले एक दशक से कल्याणी समूह की रणनीति को मूर्त रूप देने और इसके विविधीकरण के क्रियान्वयन में शामिल रहे हैं। आप कंपनी के वित्त एवं विलय तथा अधिग्रहण सम्बन्धी मामलों की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनका मुख्य ध्यान अब प्रतिभा को पोषित करने और संगठन के भीतर नए कौशल विकसित करने, रणनीति बनाने और नए क्षेत्रों और उत्पादों में विकास को बढ़ावा देने पर है। अमित कल्याणी भारत फोर्ज लिमिटेड और कल्याणी स्टील्स लिमिटेड जैसी विभिन्न समूह कंपनियों के बोर्ड में सदस्य हैं और

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भारत फोर्ज लिमिटेड के उप प्रबन्ध निदेशक अमित कल्याणी

अमित कल्याणी पिछले एक दशक से कल्याणी समूह की रणनीति को मूर्त रूप देने और इसके विविधीकरण के क्रियान्वयन में शामिल रहे हैं। आप कंपनी के वित्त एवं विलय तथा अधिग्रहण सम्बन्धी मामलों की जिम्मेदारी निभाते हैं।

बीएफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड की बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। वह विनिर्माण, शिक्षा, कौशल विकास और द्विपक्षीय संबंधों पर भारत सरकार की कई समितियों का हिस्सा रहे हैं।

अमित कैपजेमिनी, भारत के सलाहकार बोर्ड में भी हैं और शेफलर इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। अमित की सीएसआर परियोजनाओं और परोपकार में विशेष रुचि है। वह समाज को वापस देने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजनाओं में अपने व्यक्तिगत समय और संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये विशेष रूप से युवाओं को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यह इन्हें ऊर्जान्वित करता है।

अमित और उनकी पत्नी दीक्षा ने कल्याणी स्कूल की स्थापना की है। यह एक गैर लाभकारी संस्थान है जो उच्च गुणवत्तायुक्त है और आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। बाबा कल्याणी के लिए पुत्र की कारोबारी प्रगति नि:संदेह उत्साहवर्धक होगी, जो 73 वर्ष की उम्र में भी कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय हैं। बाबा कल्याणी के यशस्वी सुपुत्र अमित एक पारिवारिक व्यक्ति हैं जो अपने तीन बच्चों, पत्नी और माता-पिता के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।

◆◆◆

बेमिसाल बैंकिंग का अप्रतिम उदाहरण

इंडसइंड बैंक

एक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में, इंडसइंड बैंक कॉर्पोरेट और खुदरा बैंकिंग समाधान प्रदान करता है जो एक स्थायी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- आलोक रंजन तिवारी

किसी भी बैंकिंग इकाई का मूलभूत उद्देश्य यही होता है कि वो न सिर्फ देश की आर्थिक उन्नति में योगदान करे बल्कि वित्तीय समावेशन में भी भूमिका निभाए। इन दोनों ही मोर्चों पर देखें तो इंडसइंड बैंक का प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। इस बैंक के कार्यप्रणाली की बात करें तो इंडसइंड बैंक 28 मिलियन से अधिक ग्राहकों, पांच हजार से अधिक वितरण बिंदुओं और देश भर में लगभग दो हजार शाखाओं के साथ व्यापक बैंकिंग सुविधाओं वाला एक सार्वभौमिक बैंक है। बुनियादी तौर पर निरंतरता के साथ, इंडसइंड बैंक सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनैंस), व्यक्तिगत ऋण, व्यक्तिगत और व्यवसायिक वाहन ऋण, क्रेडिट कार्ड, लघु एवं मध्यम उद्योग ऋण सहित व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इतना ही नहीं यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्रक इकाइयों और बड़े कॉरपोरेट्स के लिए भी पसंदीदा बैंकिंग साझेदार है।

इंडसइंड बैंक अपने परिचालन और रिपोर्टिंग में एकीकृत दृष्टिकोण को शामिल करने वाले भारत के अग्रणी संगठनों में से एक रहा है। बैंक अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य को बनाने में विश्वास रखता है और इसीलिए यह 2011 से ही अपनी इच्छा से स्थिरता प्रदर्शन रिपोर्ट को सबके सामने रख रहा है। बैंक ने 2017 में अपनी पहली एकीकृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तब से इस एकीकृत रिपोर्ट को इसने प्रकाशित करना जारी रखा है जो पर्यावरण,सोशल एंड गवर्नेंस (ईएसजी) पहलुओं समेत इसकी रणनीति,प्रदर्शन संबंधों और मूल्य-निर्माण प्रयासों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

बैंकिंग संचालन के अपने 28 वें वर्ष में, यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती नवीन पीढ़ी के निजी बैंकों में से एक है। श्रीचंद पी. हिंदुजा द्वारा 1994 में स्थापित इस बैंक का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर रखा गया था जो मानव सरलता, उद्यम और व्यावसायिक कौशल के अपने सबसे बड़े सांस्कृतिक उदाहरणों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में, इस बैंक ने देश भर में अपने लाखों ग्राहकों के लिए बैंकिंग को एक आसान और उपयोगी संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया है। साथ ही अपने ग्राहकों की हर जरूरत को पूरा करने वाले अपनी तरह के सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए एकल-सोच के साथ विकसित भी हुआ है। भारत भर में इसकी कुल 2015 शाखाएँ हैं जिनमें 436 तो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इसके अलावा ये भारत भर में कुल 2872 एटीएम के माध्यम से कार्यरत है। इसी क्रम में देखें तो इसका ग्राहक आधार 28 मिलीयन, बैक कार्यालय 46 तथा कुल स्थायी कर्मचारी 29,661 हैं।

इंडसइंड बैंक अपने परिचालन और रिपोर्टिंग में एकीकृत दृष्टिकोण को शामिल करने वाले भारत के अग्रणी संगठनों में से एक रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, यह उद्योग जगत में उच्चतम गुणवत्ता मानकों के बराबर अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए निरंतर और गतिशील रूप से विकसित हुआ है। डिजिटलीकरण को अपनाने में अग्रणी स्थान रखने वाला यह बैंक अपने स्पष्ट दृष्टिकोण और उत्तरदायी व्यवहार के लिए उद्योग जगत में जाना जाता है।

वर्तमान में यह बैंक अपनी सेवाओं और उत्पाद वितरण सुविधाओं को बढ़ाते हुए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वसनीय डिजिटल मंचों के माध्यम से ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों में निवेश करके अपनी डिजिटल क्षमता को मजबूत कर रहा है। संतुलित और सुरक्षित बैंकिंग परिचालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक अपने ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी की गोपनीयता को सर्वाधिक महत्व देता है। यह साइबर सुरक्षा उपायों को लगातार बढ़ा रहा है और सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाकर अपने सूचना-प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है।

संपोषणीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, इंडसइंड बैंक ने स्थायी वित्तपोषण में कदम रखा है और कंपनियों के ईएसजी प्रदर्शन के आधार पर क्रेडिट लाइन विकसित की है। इस पोर्टफोलियो के तहत, बैंक ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें ब्याज-दरें उधारकर्ता के ईएसजी प्रदर्शन से जुड़ी होती हैं।

एक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में, इंडसइंड बैंक कॉर्पोरेट और खुदरा बैंकिंग समाधान प्रदान करता है जो एक स्थायी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैंक आसान वित्तीय समाधान प्रदान करने के साथ ही साथ स्वास्थ्य-सुविधा, शिक्षा और किफायती आवास ऋण को भी सुनिश्चित कर अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करता है। ◆◆◆

अरुण तिवारी
चेयरमैन, इंडसइंड बैंक

बैंकिंग जगत के महारथी

अरुण तिवारी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने जिन राष्ट्रीय स्तर की समितियों में कार्य किया, वे हैं - अध्यक्ष, फिक्की की बैंकिंग और वित्तीय संस्थान समिति, सह-अध्यक्ष, बैंकिंग और वित्त पर सीआईआई की समिति, अध्यक्ष,जोखिम प्रबंधन और बेसल प्रबंधन और बेसल कार्यान्वयन पर स्थायी समिति आदि।

यदि इंडसइंड बैंक की सफल विकास यात्रा को देखें तो अनिवार्य रूप से इसकी अगुआई करने वाले व्यक्तियों की चर्चा करनी होगी। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है, वह है इंडसइंड बैंक के चेयरमैन अरुण तिवारी। श्री तिवारी ने कैरियर बैंकर के रूप में उनतालीस वर्षों के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान रणनीतिक योजना, परियोजना वित्त, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, क्रेडिट संचालन आदि के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने दिसंबर 2013 से जून 2017 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे इलाहाबाद बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। अपने मूल संगठन - बैंक ऑफ बड़ौदा में, उन्होंने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में देश और विदेश के विभिन्न केंद्रों में 33 वर्षों तक काम किया। श्री तिवारी ने यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है।

अपने लंबे करियर में उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में भी काम किया है। वे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने जिन राष्ट्रीय स्तर की समितियों में कार्य किया, वे हैं - अध्यक्ष, फिक्की की बैंकिंग और वित्तीय संस्थान समिति, सह-अध्यक्ष, बैंकिंग और वित्त पर सीआईआई की समिति, अध्यक्ष,जोखिम प्रबंधन और बेसल कार्यान्वयन पर स्थायी समिति आदि।

अरुण तिवारी के पास रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि है। अपने करियर के दौरान उन्होंने विश्व बैंक के तत्वावधान में कई असाइनमेंट भी किए हैं। इसके अलावा वे केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आर्थर डी लिटिल (बोस्टन), आईएसबी(हैदराबाद), आईआईटी,(मुंबई)आदि संस्थानों के कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा भी रह चुके हैं।

कर्मठता की मिसाल

सुमंत कठपालिया

सुमंत कठपालिया
एमडी एवं सीईओ, इंडसइंड बैंक

> **सुमंत कठपालिया ने इंडसइंड बैंक को एक ग्राहक उत्तरदायी बैंक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

भारतीय बैंकिंग जगत में सुमंत कठपालिया एक ऐसे व्यक्तित्व के परिचायक हैं जिन्होंने अपनी कर्मठता एवं प्रभावी कार्यकुशलता के माध्यम से अपनी विशेष पहचान बनाई है। इंडसइंड बैंक में शामिल होने से पहले श्री सुमंत कठपालिया सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और एबीएन एमरो जैसे बड़े बहु-राष्ट्रीय बैंकों में समृद्ध अनुभव के साथ एक करियर बैंकर रह चुके हैं। इंडसइंड बैंक में शामिल होने से ठीक पहले, उन्होंने एबीएन एमरो के साथ कई महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया। एबीएन एमरो से पहले, सुमंत ने बैंक ऑफ अमेरिका में एक दशक बिताया और उन्होंने सिटी बैंक के साथ अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने बिजनेस ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी, विक्रय और वितरण, जोखिम और वित्तीय प्रबंधन सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया।

सुमंत कठपालिया एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) में स्नातक हैं। सुमंत ने अपने तीस वर्षों के करियर में कई नेतृत्वकारी भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, जिसमें व्यवसाय के विकास के साथ साथ नवाचारी उपाय अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इंडसइंड बैंक में, सुमंत कथपालिया उस कोर लीडरशिप टीम का हिस्सा हैं जो बारह साल पहले बैंक में शामिल हुई थी और बैंक में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण रही है।

सुमंत, बैंक के व्यापक वित्तीय प्रबंधन और निवेशक-संबंधों के प्रबंधन के मूल्यांकन में शामिल शीर्ष स्तरीय कार्यकारी समिति के प्रमुख सदस्य रहे हैं। इंडसइंड में प्रमुख उपभोक्ता बैंकर के रूप में अपनी पूर्व भूमिका में, सुमंत ने व्यक्तिगत और लघु एवं मध्यम उद्योग (एसएमई) क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नए व्यवसायों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही गुणवत्ता-नियामक और आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सफलतापूर्वक संतुलित और समन्वित भी किया है। सुमंत ने इंडसइंड बैंक को एक ग्राहक उत्तरदायी बैंक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह ग्राहक अनुभव को पुनर्परिभाषित करने और दक्षता के साथ आगे बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण का लाभ उठाने वाले व्यापार मॉडल को पुनर्जीवित करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

◆◆◆

PROJECT MANAGEMENT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

ARCHITECTURAL DESIGN SERVICES | INTERIOR DESIGN

A2Z ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED

Tech Park One, Tower 'E', 191 Yerwada, Pune-411 006 (INDIA)

Our learning is best when it teaches humanity but to be proud of learning is the greatest ignorance in the world.

With Best Compliments from

Umesh Gandhi

Builders & Developers

DEEPAK BUILDERS
POONAM BUILDERS
AVON BUILDERS
GEETA BUILDERS

DEEPDHARSHAN BUILDERS PVT. LTD.
JITEN AGRO LAND & FARM PVT. LTD.
SUNCITY LAND & INFRASTRUCTURE PVT.LTD
SUNRISE PARTY HALL

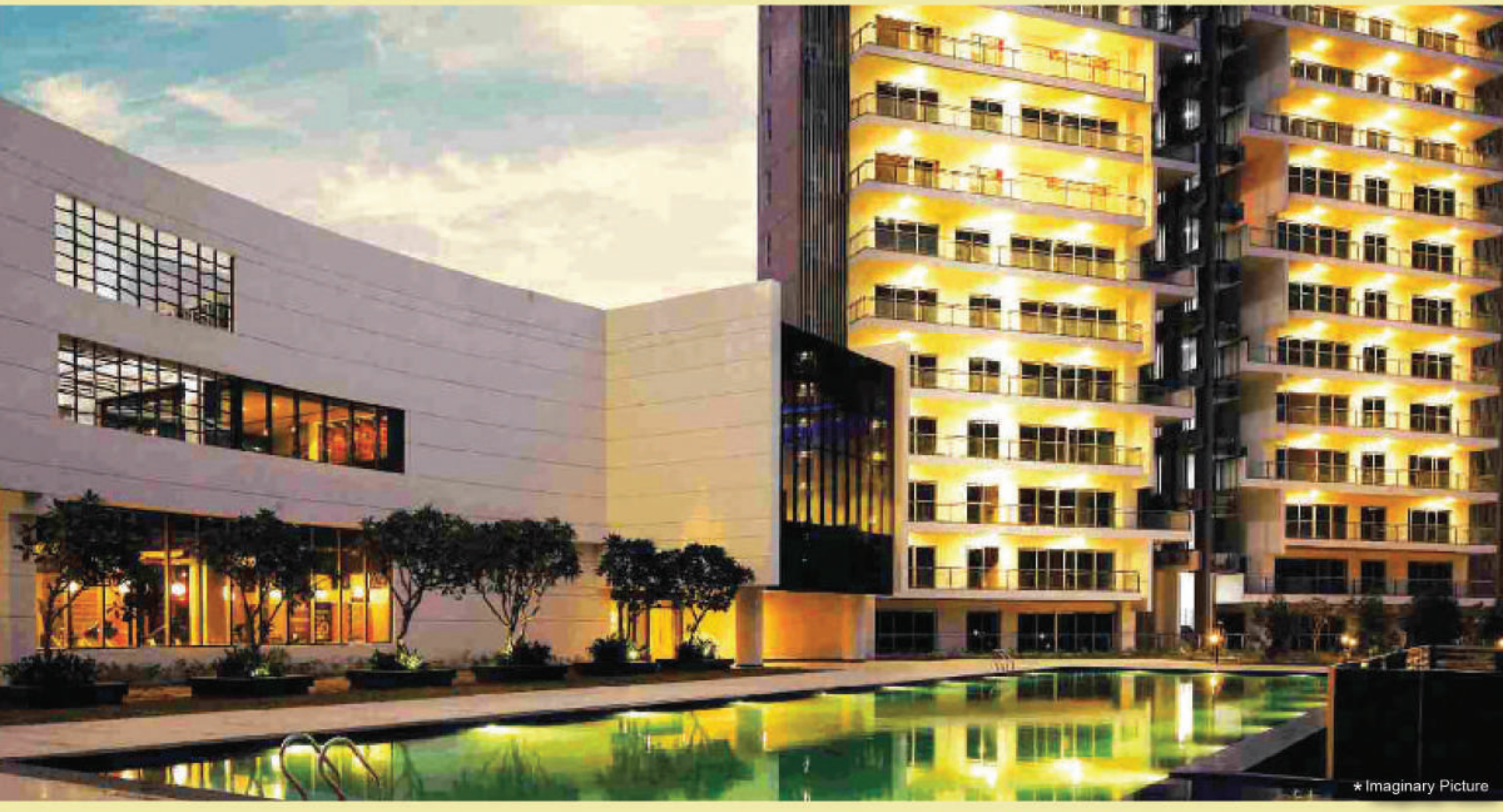

Builders, Developers & Hospitality Business

Office: B/203 Goyal Shopping Arcade, S.V.Road, Borivali (West), Mumbai - 400 092.

Tel No. 022 - 61363636 Fax No. 022 - 61363600

Email :- poonambuilders@gmail.com

* नॉर्थ ईस्ट सर्किट विकास कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला

मणिपुर के विशेष संदर्भ में उत्तर पूर्व और उसके बदलाव की कहानी

महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदिनल्यू की जन्मभूमि मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में खूबसूरत पहाड़ियों और झीलों के बीच अवस्थित है।

– उत्पल कांत

मणिपुर अब विकास की नयी इबारत लिख रहा है। मणिपुर की ऊंची-ऊंची नीली पहाड़ियों में जहाँ कभी सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती थी, वहाँ अब पक्षियों की मधुर स्वर लहरियों की गूंज सुनाई देती है।

भारत की संस्कृति जितनी वैविध्यपूर्ण है, उतना ही इसका भूगोल भी। कई बार तो भूगोल की यह सीमा इस हद तक विस्तारित नजर आती है कि दो दिशाओं के बीच समन्वय बना पाना मुश्किल हो जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का इतिहास ऐसा ही जटिल और उलझा रहा है। चाहे असम में जातीयता और प्रवासन से जुड़ी चुनौती हो या फिर नागालैंड की स्वायत्तता का या फिर मणिपुर-मेघालय में उग्रवादी मांगों की दीर्घजीविता का, इस क्षेत्र का भूगोल लंबे समय तक अशांत रहा है। अरुणाचल भी इसका अपवाद नहीं है। खासकर चीनी हस्तक्षेप के कारण यह क्षेत्र और तनावपूर्ण बना रहता है। साथ ही कहीं-कहीं अफस्पा के कारण भी गतिरोध बनता रहा है। इतनी सघन चुनौती वाले क्षेत्र में किसी भी सरकार के लिए शांति स्थापना एक गंभीर चुनौती है। लेकिन, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि लंबे समय से चल रहे नगा विवाद इस हद तक सुलझ गया कि समझौते की शर्तों के प्रति परस्पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं अन्य राज्यों के साथ भी केंद्र सरकार ने स्थानीय संस्कृति और स्वायत्तता से छेड़ छाड़ किये बिना उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता पाई है। और इसलिये ही अशांत कहा जाने वाला यह क्षेत्र आज शांतिपूर्ण समाज के रूप में व्याप्त है। इन सबके मूल में विकास कार्यों की पहुँच है। मणिपुर के विशेष संदर्भ में इसे देखना दिलचस्प होगा।

महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदिनल्यू की जन्मभूमि मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में खूबसूरत पहाड़ियों और झीलों के बीच अवस्थित है। अपने सदाबहार प्राकृतिक नजारों के लिए आभूषणों की भूमि के नाम से जाना जाने वाला मणिपुर 21 जनवरी 1972 से एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से 2017 तक राजनैतिक अस्थिरता, उग्रवाद, क्षेत्रीय संघर्ष के लिए ही जाना जाता रहा। केंद्र व राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के पहले पूर्ववर्तियों ने मणिपुर की सत्ता पर किसी तरह बने रहने के लिए मणिपुर को क्षेत्रीय संघर्षों की आग में झोंके रखा नतीजतन, ऊर्जावान मानवीय क्षमताओं और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य दिन-ब-दिन गरीबी के कुचक्र में फंसता चला गया और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए।

मणिपुर के लिए हताशा से भरे उस दौर की समाप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होने के साथ ही शुरू हो जाता है। 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का कमान अपने हाथों में लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाया, जिसका प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव सभी के सामने है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित मणिपुर अब विकास की नयी इबारत लिख रहा है। मणिपुर की ऊंची-ऊंची नीली पहाड़ियों में जहाँ कभी सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती थी, वहाँ अब पक्षियों की मधुर स्वर लहरियों की गूंज सुनाई देती है, घाटी के बड़े-बड़े घास के मैदान जो उग्रवादियों का बसेरा मात्र था वो अब सैलानियों का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले पाँच वर्षों से मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार भी है, जिसे वहाँ की जनता ने ही मोदी जी के लोकतांत्रिक नीतियों में विश्वास व्यक्त कर चुना भी है। शांति एवं प्रगति की राह पर अग्रसर मणिपुर की मासूम जनता पूर्ववर्ती सरकारों के उग्रवाद को पोषित करने वाली नीतियों को याद करके ही सहम जाती है कि तुच्छ राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह से वर्षों तक उनकी कई पीढ़ियों को विकास से कोसों दूर रखा।

जिस मोइरांग की पावन भूमि से नेताजी सुभाषचंद्र चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भारत वर्ष में प्रवेश कर तिरंगा फहराया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया वो

आजादी के 75 वर्षों के बाद भी सड़क, बिजली, पानी,अस्पताल,विद्यालय, संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही। मणिपुर के लोगों की सबसे बड़ी समस्या स्वच्छ पेयजल के उपलब्धता की थी। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच विशेषकर ग्रामीण इलाकों में साफ पीने के पानी के व्यवस्था में लोगों का पूरा दिन निकल जाता था। इस राज्यव्यापी समस्या के समाधान हेतु जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा की गई। जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हर घर तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। ये जलापूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे इसके लिए 280 करोड़ की लागत से थाउबेल बहुउद्देश्यीय परियोजना मणिपुर राज्य को समर्पित किया गया। इससे इम्फाल ईस्ट एवं इम्फाल वेस्ट जिलों में स्वच्छ पेयजल की समस्या पूर्णत: समाप्त हो गयी। वहीं 65 करोड़ की लागत से तोमंगलोंग जिले में और 58 करोड़ की लागत से सेनापति जिले में भी पेयजल के परियोजनाओं की शुरुआत की गयी। इन परियोजनाओं के शुरू होने के पहले मणिपुर में मात्र 6 प्रतिशत घरों तक पेयजल की आपूर्ति हो पाती थी और आज जल जीवन मिशन योजना के तहत 70 प्रतिशत घरों में चौबीसों घण्टे स्वच्छ पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किया जा चुका है। जल्द ही शत प्रतिशत आबादी तक स्वच्छ पेयजल की पहुँच हो जाएगी।

मणिपुर पहले देश के उन क्षेत्रों में शुमार था जहाँ सड़क मार्ग से पहुँच साल के बारहों महीने तक सम्भव नहीं था और इस गंभीर समस्या से अभिशप्त मणिपुरवासियों को निजात दिलाने के लिए डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा एनएच 37 पर पड़ने वाली बराक नदी पर 75 करोड़ की लागत से इस्पात पुल का निर्माण किया गया। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल को असम के सिलचर से जोड़कर ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। साथ ही प्रदेश में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 4148 करोड़ रुपये की लागत से 298 किलोमीटर लम्बाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है, जो मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों के साथ हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वहीं इन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत भारत के प्रवेश द्वार के तौर पर निर्मित हो रहे इम्फ़ाल–मौरे हाइवे यानी एशियन हाईवे वन का निर्माण कार्य भी अत्यंत तेजी से चल रहा है। ये हाइवे जहाँ साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा वहीं इसके चालू होते ही मणिपुर देश भर में व्यापार और निर्यात के प्रमुख स्थान के रूप में जाना जायेगा, जो मणिपुर के सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

एक समय मणिपुर के लोगों के लिए ब्रॉडगेज रेल किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूर्वोत्तर विकास रेलवे के द्वारा मणिपुर को देश ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया और दो साल के भीतर ही असम के सिलचर से मणिपुर के जिरिबाम के बीच ही इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को पूरा कर लिया गया। 27 मई, 2016 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहली ब्रॉडगेज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गयी। जल्द ही मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है जिसके लिए लगभग 13000 करोड़ की लागत से 111 किलोमीटर लंबे जिरिबाम–तुपुल–इंफाल रेललाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा ही होने वाला है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल(141मीटर) भी बनाया जा रहा है। जिरिबाम –इम्फाल रेलवे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। भविष्य में इस

मणिपुर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से शायद ही प्रदेश के किसी हिस्से में बंद, हड़ताल, नाकेबंदी जैसे शब्द कभी सुनाई दिये हों।

योजना का विस्तार पड़ोसी देश म्याँमार तक किया जाना प्रस्तावित है, जिससे मणिपुर को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर भारत को और अधिक मजबूत किया जा सके।

तकनीक के इस युग में किसी राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए वहाँ बेहतर संचार व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि मणिपुर काफी समय तक अछूता ही रहा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उसके प्रत्येक हिस्से तक सुपर कनेक्टिविटी वाले इंटरनेट व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है, इसे ही आधार मानकर मणिपुर की दुर्गम पहाड़ियों के बीच भी बेहतरीन इंटरनेट और कॉलिंग की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1100 करोड़ की लागत से 2350 मोबाइल टावरों की आधारशिला रखी है। कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक तक भारत के तिरंगे झंडे का मान बढ़ाने वाली बेटियों कुंजरानी, मैरीकॉम ,मीराबाई चानू की उर्वर भूमि का नाम मणिपुर है, जिन पर पूरा देश गर्व महसूस करता है। इन खिलाड़ियों से सीखने और खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण देकर नई–नई प्रतिभाओं को तराशने के लिए मणिपुर में देश के पहले आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गयी है। अपने आबादी के अनुपात में सर्वाधिक खेल बजट पूरे देश भर में मणिपुर राज्य का है जिसका श्रेय मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह की सरकार को जाता है, जिन्होंने राज्य का खेल बजट का आकार बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये का कर दिया, जिससे राज्य में खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं से मणिपुर निवासियों को भी काफी राहत मिली है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य में 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न सुविधा का लाभ मिल रहा है ,वहीं उज्ज्वला योजना के तहत डेढ़ लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिया जा चुका है। साथ ही राज्य के गरीबों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 80 हजार घरों के निर्माण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। मोदी जी के स्वस्थ भारत मिशन के तहत संचालित आयुष्मान भारत योजना से अभी तक साढ़े चार लाख लोग मणिपुर में लाभान्वित हो चुके हैं।

ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का आह्वान और उनके द्वारा किये गये पूर्वोत्तर भारत के विकास का संकल्पित प्रयास ही है कि मणिपुर के लाखों भटके नौजवान हिंसा और अलगाव की राह को छोड़ शांति और एकजुटता के मार्ग पर चल विकासशील से विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं मणिपुर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से शायद ही प्रदेश के किसी हिस्से में बंद, हड़ताल,नाकेबंदी जैसे शब्द कभी सुनाई दिया हो। ब्लॉक्ड स्टेट की नकारात्मक छवि से बाहर आकर मणिपुर वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मार्ग प्रशस्त करने वाला राज्य बन चुका है। ◆◆◆

बदलता सिनेमा इसका इतिहास और निहितार्थ

– कुमार गौरव

आरंभिक भारत के निर्माण में एक तरफ जहाँ गांधी और नेहरू एक दूसरे से सहमति का विशाल क्षेत्र निर्मित करते थे वहीं दूसरी तरफ आजादी के बाद एक ऐसा विषय भी आया जहाँ दोनों के विचारों में भिन्नता थी। यह द्वंद सिनेमा में भी दिखता है।

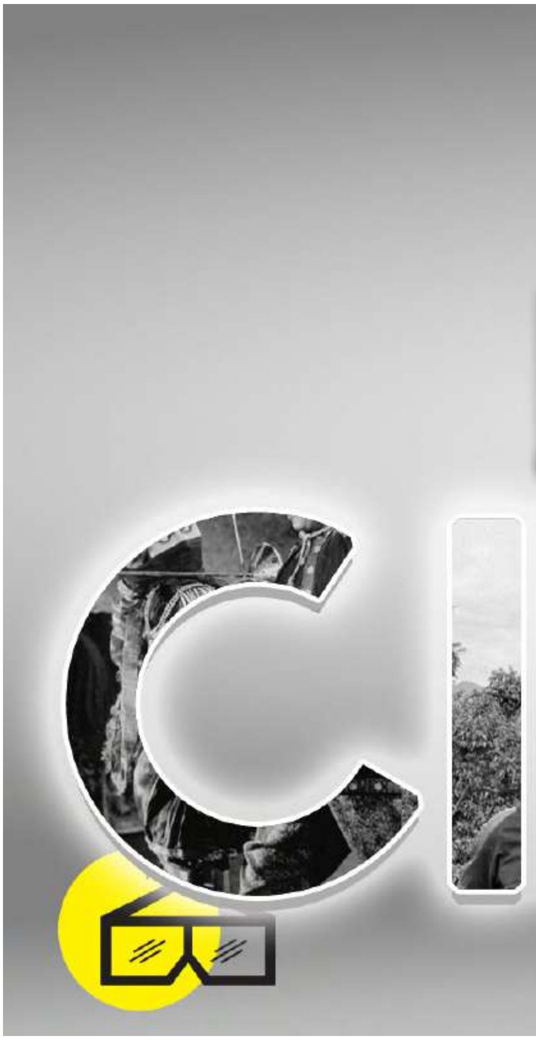

सिनेमा को अक्सर ही राजनीति से अलग एक सांस्कृतिक निर्मिति के रूप में देखा जाता है लेकिन सच्चाई यह है कि यह गहरे तौर पर राजनीति से प्रेरित और संचालित होता है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो जिस किस्म का राजनीतिक परिवेश है, सिनेमा का व्याकरण भी उसी अनुरूप रूपांतरित हो रहा है। हिंदू विषय से सायास दूरी की हिचक टूटी है और ऐसे विषयों पर फिल्में बनने लगी हैं जिन्हें पहले सांप्रदायिक तक मान लिया जाता था। प्रस्थान बिंदु के रूप में कश्मीर फाइल्स और आरआरआर जैसी फिल्मों को रख लेते हैं। चूँकि मैं एक शोधार्थी हूँ इसलिये मेरा मूल जोर इस सैद्धांतिकी पर है कि सिनेमा और राजनीति आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। वर्तमान की स्थिति अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी।

दरअसल, अपनी विशिष्ट दृश्य प्रभाव के कारण सिनेमा संप्रेषण के अन्य किसी भी माध्यम से कहीं अधिक विस्तृत और प्रभावशाली होता है। खासकर, आम जनमानस के विचारों को प्रभावित करने में इसका कोई विकल्प नहीं है। वस्तुत: संवाद प्रयोग और उसको पुष्ट करते दृश्य प्रभाव लंबे समय तक दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ता है और निरंतर यही प्रक्रिया दोहराई जाए तो किसी विषय के प्रति कोई छवि निर्मित की जा सकती है। यही वजह है कि सिनेमा का उपयोग प्रभाव उत्पन्न कर सकने वाले एक उपकरण के रूप में किया जाने लगा। जाहिर है कि राजनीति इससे और यह राजनीति से प्रभावित होगी ही। वर्तमान इसका अपवाद क्यों हो?

वस्तुत: एक राष्ट्र के रूप में हम

कौन हैं? की पड़ताल हमेशा से विवाद और जिज्ञासा का विषय रहा है। राज्य से लेकर समाज तथा फिल्मकार से लेकर बौद्धिक वर्ग सब अपने अपने तरीके से इसकी खोज करते हैं। कई बार ये सभी कुछ भिन्नताओं के साथ वृहद रूप से एकता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ही हम देखते हैं कि इस हम की खोज में सिनेमा बहुधा राज्य की परियोजना के साथ सहयुग्मित हो जाता है। अब अगर एकदम शुरुआत से देखें तो यद्यपि भारत ने आजादी के बाद स्वयं को एक सेकुलर राज्य के रूप में स्थापित किया किंतु यह भी सच है कि इसका एक हिस्सा धर्म के नाम पर अलग हुआ था। इसलिए राज्य और समाज दोनों के लिए इस भावना को मजबूत करना था। साथ ही पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू राष्ट्र निर्माण की योजना को समाजवादी तरीके से लागू करना चाहते थे। उस दौर के सिनेमा में राज्य के प्रयासों की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वस्तुत: सिनेमा इस राष्ट्रवादी परियोजना का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर रहा था। इतना ही नहीं स्वतंत्रता के शुरुआती तीन दशकों में राज्य निर्माण की सांस्कृतिक परिघटना सिनेमा के भीतर गरीबी का उत्सव मनाना, वर्ग संघर्ष को तरजीह देना, संपन्नशील वर्ग को सामाजिक बुराइयों का दोषी बताने जैसे रूपकों के माध्यम से व्यक्त हो रहा था। साथ ही यह वही दौर था जब राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का भी प्रस्तुतीकरण हो रहा था। एक आम धारणा है कि 1950 और 1960 के दशकों में हिंदी सिनेमा अपने स्वर्णिम काल से गुजर रही थी।

आरंभिक भारत के निर्माण में एक तरफ जहाँ गांधी और नेहरू एक दूसरे से सहमति का विशाल क्षेत्र निर्मित करते थे वहीं दूसरी तरफ आजादी के बाद एक ऐसा विषय भी आया जहाँ दोनों के विचारों में भिन्नता थी। यह द्वंद सिनेमा में भी दिखता है। दरअसल, नेहरू राष्ट्र निर्माण में शहरों का विकास अपरिहार्य मानते थे, वहीं गांधी गांवों के प्रति अधिक आकर्षित थे। चार्ली चैप्लिन जैसा महान फिल्मकार गांधी की प्रेरणा से मॉडर्न टाइम्स रचता है जिसमें आधुनिक सभ्यता की मशीनी निर्भरता पर करारा व्यंग्य है। गांधी के सामने स्पष्ट था कि उपनिवेशवाद को उसके आधुनिक दुर्ग शहर में ही परास्त करना होगा। लेकिन, उनके लिए जीत का अर्थ अंग्रेजों के खाली शहरों में बस जाना नहीं था। उनके विचार से भारतवासियों के लिए आजादी का मतलब था शहर को अस्वीकार करना और भारत की चिरंतन सभ्यतामूलक शक्तियों को एक बार फिर हासिल करने के लिए गांव के अभयारण्य में लौट जाना चाहिए। दूसरी तरफ नेहरू के नेतृत्व में भारत आधुनिक सभ्यता को अपनाता चला गया।अपनाने की यह प्रक्रिया सिनेमा में चली इसलिए आधुनिक सभ्यता के क्षेत्र शहरों के

प्रति सिनेमा का मोह साफ तौर पर दिखता है। प्रारंभिक दौर के सिनेमा में शहर बदलाव के केंद्र और उम्मीद की किरण के तौर पर दिखता है।

जागते रहो, प्यासा, गाइड, अब दिल्ली दूर नहीं जैसे कई फिल्में उस दौर में बनीं जिसके केंद्र में शहर था। हालाँकि, यहाँ इस बात को भी रेखांकित करने की जरूरत है कि एक तरफ जहाँ शहर उम्मीद के प्रतीक के रूप में उभरता वहीं दूसरी तरफ शहर में एक खलनायक की छवि भी उभरती है। उदाहरण के लिए जागते रहे में एक आधुनिक शहर कलकत्ता में गांव से आए व्यक्ति को अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरी रात मशक्कत करनी पड़ती है। और इसी एक रात में यह भी दिखता है कि यह आधुनिक शहर जितनी उन्नति का उजाला दिखाता है, अपराध और निराशा की तहें भी यहाँ उतनी ही गहरी हैं। इसी प्रकार गाइड में जेल से छूटकर नायक गांव की ओर ही जाता है। गुरूदत्त की प्यासा याद करें तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है के साथ आधुनिक व्यवस्था के प्रतीक शहर के प्रति एक वितृष्णा का भाव। यह निश्चित नहीं है कि नायक कौन सी दुनिया चाहता है पर नायक शहर नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त भले ही सिनेमा का केंद्र शहर रहा किंतु अधिकांश नायक शहर का बाशिंदा न होकर गांव से आया व्यक्ति होता था। राजकपूर की फिल्मों में तो गांव छूटने का मोह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अर्थात् भले ही शहर को भविष्य के रूप में देखा जा रहा था किंतु पृष्ठभूमि में गांव ही था। इस प्रकार रूपहले पर्दे पर गांव शहर के द्वंद के बीच बनते राज्य निर्माण को साफतौर पर देखा जा सकता है।

शहर–गांव के द्वंद्व के इतर राज्य निर्माण सत्ता के प्रति सामाजिक वैधता को प्राप्त करने की दिशा में भी हो रहा था। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया एकतरफ चुनी हुई सरकार के प्रति जनआकांक्षा के रूप में विकसित हो रही थी तो साथ ही इसका स्वरूप सेकुलर था। यह सेकुलर स्वरूप राजसत्ता का धर्म के ऊपर वर्चस्व के रूप में विकसित हो रहा था। अब दिल्ली दूर नहीं रूपहले पर्दे पर ऐसा ही रूपक रचता है, जब आधुनिक राष्ट्र राज्य के प्रतीक नेहरू और इस सत्ता का केंद्र दिल्ली आम जनता की उम्मीदों का अंतिम केंद्र बन जाता है। पंडित नेहरू जी को कौन नहीं जानता। वो हम सबके माई बाप हैं। कहूंगा कि आप जैसे

वर्तमान में सिनेमा में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो अपने समय से सुसंगत ही हैं। अपने समय को व्यक्त करने की सिनेमाई इच्छा ही कश्मीरी फाइल्स और आरआरआर जैसी फिल्मों में व्यक्त हो रही है।

इंसाफ के देवता के होते हुए आपके एक बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है। यहाँ आधुनिक राष्ट्र राज्य अब इंसाफ का देवता है। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता के प्रति सामाजिक निष्ठा का आरोपण सिनेमा में हो रहा था। वस्तुतः यह नेहरू के राष्ट्र का ही रूपांतरण था।

राष्ट्र निर्माण के उस दौर में धर्म और आस्था के प्रश्न से भी जूझना था। नेहरूवादी राष्ट्र राज्य सेकुलर मॉडल में विकसित हो रहा था किंतु वह धर्म की समाप्ति का भी पक्षधर भी नहीं था। आस्था के मामले में संवैधानिक मान्यता भी यही थी। इस संवैधानिक मान्यता से इतर देखें तो तत्कालीन समाज अत्यधिक धार्मिक था तथा राज सत्ता को इससे सामंजस्य स्थापित करना था। सिनेमा में भी यह सामंजस्य गाइड जैसी अनुकृति के माध्यम से पूरा हो रहा था। शहर से आया और आधुनिक शिक्षा प्राप्त राजू गांव का समुच्चय विश्वास जो आस्था के रूप में घनीभूत होता है का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिकता की तर्क प्रणाली और धार्मिकता की आस्था के द्वंद्व के निष्कर्ष के रूप में जब नायक का गांव बसता है तो दरअसल राज्य निर्माण के उसी सामंजस्य की परियोजना पूरी होती है। आजादी के शुरूआती पांच दशक का सिनेमा काफी हद तक आदर्शवाद से प्रेरित रहा। इसके बाद का समय विशेषकर साठ के दशक के अंत से यह प्रवृत्ति कम होने लगती है। राजनीतिक प्रणाली से भी नेहरूवादी आदर्श कम हो रहे थे तथा सत्ता संरचना नई किस्म की बुराइयों से ग्रस्त होता है। यह वही दौर था जब सामाजिक असंतोष से नक्सलबाड़ी जैसा विप्लव देखने को मिलता है और इसका प्रभाव सिनेमा पर भी दिखता है। एंग्री यंगमैन वाले नायक का पर्दे पर आगमन होता है जो अक्सर कानूनी दायरे से इतर न्याय करता है। यह दौर एक यथार्थ कैरेक्टर का निर्माण करता है। फिर देश आपातकाल को झेलता है।

तो वर्तमान में सिनेमा में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो अपने समय से सुसंगत ही हैं। अपने समय को व्यक्त करने की सिनेमाई इच्छा ही कश्मीरी फाइल्स और आरआरआर जैसी फिल्मों में व्यक्त हो रही है। यद्यपि सिनेमा की यह राजनीति भी आलोचना से परे नहीं है लेकिन इतने विस्तार से सिनेमा के ऐतिहासिक विकासक्रम को प्रस्तुत करने का उद्देश्य भी यही था कि इसकी स्वाभाविकता को ठीक से समझ लिया जाए। हालाँकि बदलाव के हिसाब से देखें तो शुरुआत भर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सिनेमा आने वाले समय में किस तरह परिवर्तित होती है।

(लेखक इतिहास के शोधार्थी हैं)

◆◆◆

AJMERA
Built on Trust

100 acres interconnected, integrated new age living destination in the heart of Mumbai city

AJMERA
i-LAND
WHERE FUTURE LIVES
WADALA (E)

2,3 & 4 BHK Available

SPRAWLING SPORTS ACADEMY | INDEPENDENT CLUBHOUSES | UPCOMING SCHOOL AND COMMERCIAL AVENUES

Planned by the world renowned New York based architects, Skidmore, Owing & Merrill LLP (SOM), the designers of Dubai's Burj Khalifa

SITE: AJMERA i-LAND, NEXT TO I-MAX BHAKTI PARK, WADALA (E) • E: iland@ajmera.com • W: www.ajmera.com

Visit us to know more or call:
9699 095 095

49 years of fulfilling dreams | 40,000 homes of happiness | 45 million sq. ft. of development • Mumbai | Pune | Bangalore | Ahmedabad | Bahrain

Disclaimer: All the specifications, designs, facilities, dimensions etc. are subject to the approval of the respective authorities. The developers reserve the right to change the specifications or features without any notice or any obligation. Images are for representative purpose only.

Project funded by HDFC ICICI Bank

Follow Ajmera Realty on Linked in

हाईकोर्ट को मिलेंगे 15 जज : कॉलेजियम से मिली मंजूरी

दिल्ली-पटना के लिए 7-7 और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए एक नाम

दिल्ली के सात वकीलों को हाईकोर्ट जज के रुप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। सीजेआई जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 4 मई को हुई बैठक में इनके नामों को मंजूरी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जिन वकीलों को जज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उनमें, विकास महाजन, तुषार राव गेडेला, मनमीत प्रीतम सिंह अरोडा, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरांग कंठ और सौरभ बनर्जी के नाम शामिल हैं। इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 35 है। यहां जजों के कुल 60 पद हैं। पटना में 7 नाम मंजूर इसी तरह पटना हाईकोर्ट में ज्यूडिशियल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे 7 लोगों को भी हाई कोर्ट में जज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा,जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्् मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा के नाम शामिल हैं।

आंध्र में एक जज का प्रस्ताव मंजूर

वहीं आंध्र प्रदेश के एडवोकेट मेहबूब सुभानी शेख को हाई कोर्ट जज के रुप में नामित करने के प्रस्ताव को भी कॉलेजियम ने मंजूदी दी।

यह है योग्यता

बता दें कि किसी हाई कोर्ट में जज के बनने के लिए लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 10 साल तक न्यायिक पर कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, हालांकि 62 बर्ष की आयु पूरी नहीं हो। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और अन्य जज होते हैं। जहां चीफ जस्टिस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उससे पहले भारत के सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श जरूर लिया जाता है। इसके बाद राज्यपाल इसके संबंध में प्रधानमंत्री से परामर्श करके उस राज्य के हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करता है।

झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की अमीषा पटेल की याचिका

● ढाई करोड़ के धोखाधड़ी में नहीं मिली राहत, चेक बाउंस का मामला

फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में अमीषा पटेल की याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को धोखाधड़ी मामले में किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया है। इसको उनकी ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। इससे पूर्व 28 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई में हुई थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। गुरुवार को फिर से इस मामले की सुनवाई हुई।

कुछ ऐसा है पूरा मामला

अमीषा पटेल के खिलाफ रांची जिले के हरमू के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि अजय कुमार सिंह को अमीषा पटेल ने फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर दिया था। फिल्म देशी मैजिक बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को ढाई करोड़ रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किया था।

जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा रूस

युक्रेन नेता 8 मई को करेंगे जेलेंस्की के साथ वर्चुअल बैठक

रूस-यूक्रेन जंग पिछले 70 दिनों से जारी है। रूस के सैनिक यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। हाल ही में रूस ने न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास किया। जिससे यूक्रेन में परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया। इसी बीच अब रूस का कहना है कि उसकी सेना यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले नहीं करेगी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जैतसेव ने कहा कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इधर, 8 मई को जी 7 नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे।

पुतिन की गर्लफ्रेंड पर बैन लगाने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन

रूस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत पश्चिमी देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के नजदीकी लोगों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसी क्रम में यूरोपियन यूनियन पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना काबेवा और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रिआर्क किरिल पर बैन की तैयारी कर रहा है। किरिल ने यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन को आशीर्वाद दिया था। पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और एक्स जिमनास्ट अलीना काबेवा के स्विट्जरलैंड में छिपे होने का दावा किया जाता रहा है।

रूस-यूक्रेन जंग के प्रमुख अपडेट्स

- डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने रूस के 8 टैंक और 5 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया है। वहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हम पर 2,000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं।
- रूस ने क्रामटोरस्क शहर में यूक्रेनी हथियार डिपो और एक मिग-29 को तबाह कर दिया।
- बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस यूक्रेन में चल रहे रूस के विशेष सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा।
- आज मारियुपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट से 500 लोगों को बाहर निकाला गया।
- यूरोपीय संघ रूसी तेल पर बैन लगा सकता है, लेकिन हंगरी इस प्रतिबंध के समर्थन में नहीं है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा कि ऐसा करना हमारी अर्थव्यवस्था पर परमाणु बम गिराने जैसे होगा।
- जर्मन चांसलर ने बताया कि जर्मन विदेश मंत्री जल्द ही यूक्रेन का दौरा करेंगे।

जॉर्ज बुश ने जेलेंस्की को बताया आज का चर्चिल

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से वर्चुअली बात की। इसके अलावा बुश ने सोशल मीडिया पोस्ट में जेलेंस्की की तारीफ करते हुए उन्हें आज का विंस्टन चर्चिल बताया है। बुश ने लिखा– जेलेंस्की की लीडरशिप और आजादी के लिए उनकी प्रतिबद्धता तारीफ के काबिल है।

शरणार्थियों के साथ मदर्स डे मनाएंगी जिल बाइडेन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन 8 मई को स्लोवाकिया में यूक्रेनी शरणार्थियों के साथ मदर्स डे मनाएंगी। जिल बीते रोज रोमानिया और स्लोवाकिया की चार दिन की यात्रा पर रवाना हुई हैं। दूसरी तरफ मारियुपोल के स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का सिलसिला 6 मई से फिर शुरू होगा।

जंग में अब तक 220 बच्चों की मौत

इधर, यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग की शुरूआत से अब तक 223 बच्चों की मौत हो गई है। 400 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा 139 बच्चों की मौत डोनेट्स्क क्षेत्र में हुई। कीव में 116, खार्किव में 95 और खेरसॉन में 46 बच्चों ने जान गंवाई है। जानकारी के मुताबिक, यूक्रेन में 6,731 नागरिक हताहत हुए हैं।

◆◆◆

Swimming Pool

Ample Car Parking

Podium Garden

Health & Fitness Center

Luxurious 2, 3 & 4 BHK Apartments

Centrally located in the heart of the city (Wadala, West), Desai Harmony makes your life convenient as the best of the metropolis surrounds you. It's a two minutes drive from all the major infrastructure facilities and the most happening destinations of Mumbai. **Stay closer to life.**

Call :+91 9209206206 / +91 75061 18929 / +91 98198 51644

E : sales@sparkdevelopers.in | sms Spark Wadala to 56677

Our Projects At : Worli | Andheri | Ghatkopar | Vile-Parle

Site Address : Desai Harmony, G.D Ambekar Marg, Opp. Hanuman Industrial Estate, Near Dadar Workshop, Wadala, Mumbai - 400 031

Corp. Office : 102, Saroj Apartment, 1st Floor, N.P. Marg, Opp. Matunga Gujarati Club, King's Circle, Matunga, Mumbai – 400 019

SPARK DEVELOPERS
creating world for you

www.sparkdevelopers.in

Disclaimer: This advertisement is merely conceptual and is not a legal document. It cannot be treated as a part of final purchase agreement. All dimensions are approximate and subject to construction variances. The developer reserves sole rights to amend architectural specifications during development stages.

BLUE STAR

NOBODY COOLS BETTER™

AN AC SO PRECISE, IT COOLS IN DECIMALS.

10792521

INDIA'S FIRST PRECISION INVERTER ACs

52°C	23.5°C	0% Finance			
Cools up to 52°C	Precision Cooling Technology	8 to 20 EMI options ₹0 down payment	Free Standard Installation#	5% Cash Back on Credit/ Debit Cards**	Up to ₹10000 Exchange Offer##

With over seven decades of expertise in air conditioning, Blue Star takes cooling to a whole new level. With a range of Inverter ACs that are so precise they allow you to change the temperature in decimal points. So that you can set the temperature just the way you want it, right down to the last decimal. These precision inverter ACs also let you save 40%^^ more power and give stabiliser^ free operation. So enjoy comfort without the slightest degree of compromise.

Visit us at: **www.bluestarindia.com** or SMS **'COOL'** to **57575** or call us at: **1800 209 1177** (toll free).

^^40% power savings in 5 star rated inverter ACs as compared to 1 star rated fixed speed ACs, under standard test conditions. ^No need for external voltage stabilisers since Blue Star inverter ACs can withstand power fluctuations within 160V to 270V. #Applicable for all WACs and SACs up to 1.5T capacity, for installations in residential / household usage only. *Multiple options from 8 to 20 months EMI. No Processing Fees. ₹ 0/- Down Payment option also. Finance solely at the discretion of the lending company and the scheme availability in a particular location or store. **5% Cashback offer is valid on full swipe transactions (i.e. Non-EMI/Finance options) of select participating bank debit and credit cards. The offer is available at select locations and at select stores on transactions made using the Brand EMI option on Pine Labs terminals. Cashback shall be credited on or before 90 business days from the date of the transaction on best effort basis to active accounts only. ##Up to ₹10000 discount on the MRP of the new product against the exchange of old AC in working condition of similar tonnage and type. As per the Government rules on e-waste and protection of environment, the recyclable materials in the old AC will be recycled or disposed in environmentally friendly manner through Government authorised e-waste service providers. For more information please call 1800 209 1177.

TITELNO. MAHHINO7214/13/A2009-TC ■ REGISTRATION NO : MAHHIN/2009/30744
BY OFFICE THE REGISTRAR OF NEWS PAPERS FOR INDIA,
MINISTRY OF INFORMATION & BRODCASTING, GOVT.OF INDIA